घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 24- शुक्रवार 27- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

सपा ने जारी किया चुनावी घोषणा-पत्र

पुरानी पेंशन की बहाली,बेरोजगारों को 5 हजार मासिक भत्ता,किसानों की कर्जमाफी का भी वादा...



लखनऊ,26 नवम्बर 2026। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने चुनावी एजेंडे में युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर गुरुवार को चुनावी घोषणा-पत्र (सत्ताईस का संकल्प) जारी करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली, बेरोजगार युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये भत्ता, किसानों की कर्जमाफी और शहरी क्षेत्रों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। घोषणा-पत्र में रोजगार,सामाजिक सुरक्षा,कृषि, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। कर्मचारियों को साधने के लिए सपा ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा किया है। वहीं,युवाओं के लिए पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने और दो से तीन करोड़ युवाओं को अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने तथा पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए समाजवादी कैंटीन शुरू करने की भी घोषणा की गई है। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में कृषि क्षेत्र में किसानों की कर्जमाफी,23 फसलों और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी तथा गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया है। बुजुर्ग महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। कानून-व्यवस्था और भूमि विवादों पर सख्त रुख अपनाने का संकेत देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर गुंडागर्दी, माफियागिरी, अवैध वसूली, धमकी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आईआरसीटीसी घोटाला मामला

लालू परिवार को बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार



नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। यह आदेश राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा 13 अक्तूबर,2025 को पारित किया गया था। इसमें भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों के लिए आरोप तय करने का निर्देश था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा है।

संसद का सत्र फिर बुलाएगी केंद्र सरकार

लोकसभा 30 नवंबर और राज्यसभा 2 दिसंबर से बैठेगी,3 दिसंबर तक चल सकता है कामकाज

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। सरकार ने संसद के दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने की तैयारी कर ली है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू कराने का अनुरोध किया है। इसके तहत लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को बुलाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि जरूरी सरकारी कामकाज निपटाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

सरकार ने दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने के लिए प्रस्ताव दिया

- **लोकसभा:** 30 नवंबर 2026, सोमवार से बैठक शुरू कराने का अनुरोध।
- **राज्यसभा:** 2 दिसंबर 2026, बुधवार से बैठक शुरू कराने का अनुरोध।
- **संभावित समापन:** दोनों सदनों का कामकाज 3 दिसंबर को समाप्त हो सकता है।
- **उद्देश्य:** जरूरी सरकारी कामकाज को पूरा करना।

महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़ा बिल लाने की अटकलें

इस बीच संसद में महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा है। इसे लेकर संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाए जाने की अटकलें थीं। ऐसे में दोनों सदनों की बैठक बुलाए जाने को इस विधेयक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, सरकार ने अभी तक बैठक के एजेंडे में इस विधेयक को शामिल करने की पुष्टि नहीं की है।

3 दिसंबर तक ही चलेगा संसद का कामकाज?

रिजिजू ने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया है कि दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर को समाप्त हो सकती है। हालांकि,उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी बताई है। उनके अनुसार, बैठकें सदनों के सामने मौजूद कामकाज की जरूरतों और परिस्थितियों के आधार पर समाप्त होंगी। इसका मतलब है कि 3 दिसंबर की तारीख संभावित है,इसे अंतिम और तय तारीख नहीं बताया गया है।



दलों के समर्थन की कितनी दरकार? समीकरण क्या?

संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए 543 सदस्यीय लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत (361 वोट) आवश्यक है। मौजूदा समय में एनडीए के पास 320 सांसद हैं। अप्रैल में बिल गिरने के बाद 26 विपक्षी सांसद (20 तृणमूल कांग्रेस और 6 उद्धव गुट) एनडीए के पाले में आ चुके हैं। फिर भी, सरकार को बिल पास कराने के लिए डीएमके (22) और एनसीपी-एसपी (8) जैसे दलों के समर्थन की दरकार होगी। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जा सकता है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष आक्रामक है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है।

परिसीमन और सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव

सतारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक पर बहस और मतदान तभी संभव होगा जब सदन व्यवस्थित तरीके से काम करेगा। मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक के लिए दो दिन और नए सत्र के लिए 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिसके तहत लोकसभा सीटों को राज्यों में 50 फीसदी बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की परिसीमन के निहितार्थों पर चिंताओं को दूर करना है।

तिरुपति में चेन्नई के दंपती ने 121 किलो सोना चढ़ाया

कीमत करीब 208 करोड़ रुपए,इस मंदिर में किसी भक्त का सबसे बड़ा दान



नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। तिरुमला के तिरुपति मंदिर में चेन्नई के एक भक्त ने गुरुवार को 121 किलो सोने के आभूषण दान किए। इनकी कीमत करीब 208 करोड़ रुपए है। यह दान वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने दिया है। दान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में हुआ। दान में 9 सेट में रखे 45 जेवर और 238.2 कैरेट के हीरे शामिल हैं। दंपती ने मंदिर में भगवान वेंकटेश का मुकुट और पैरों के आभूषण भी चढ़ावे में दिए। TTD के मुताबिक, तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर को किसी एक भक्त की ओर से दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है।

जैन ने कंपनी में अपना हिस्सा बेचा, उसी रकम से जेवर बनवाए : चेन्नई की कंपनी 'वारा फ्यूचर एलएलपी' के चेयरमैन वर्धमान जैन ने 121 किलो सोना दान किया। वर्धमान ने कंपनी में अपनी 60% हिस्सेदारी बेचकर 6000 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इसी रकम में से वर्धमान ने भगवान श्री वेंकटेश्वर को यह सोना दान किया।

कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरव दास के खिलाफ लुकआउट नोटिस...सरकार बोली...पासपोर्ट पर पिता के नाम का कॉलम खाली,जन्मस्थान और पते में भी फर्क

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास फिलहाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सरकार के मुताबिक, उनके पासपोर्ट में पिता के नाम का कॉलम खाली है। इसके अलावा जन्मस्थान, पढ़ाई और पते से जुड़ी जानकारियों में भी अंतर मिला है। सरकार ने कहा कि इन गड़बड़ियों का असर उनकी नागरिकता पर भी पड़ सकता है। दरअसल,23 नवंबर को सौरव को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था। उन्हें ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में 'कॉकरोच मूवमेंट' पर बोलना था। इसके बाद 24 नवंबर को सौरव दास ने विदेश जाने से रोके जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। दास के वकील अखिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सौरव को लुकआउट नोटिस जारी होने या विदेश जाने से रोकने के बारे में पहले



नहीं बताया गया था। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर नोटिस दिया गया। इससे पहले इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें फ्लाइट में बैठने से रोक दिया था। वकील ने कोर्ट से लुकआउट नोटिस जारी करने की वजह बताने और उसकी कॉपी देने की मांग की। इस पर केंद्र ने कहा कि लुकआउट नोटिस की कॉपी नहीं दी जा सकती। हालांकि, अब दास को इसकी जानकारी है और वे इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 23 नवंबर को शाम 7:32 बजे दास को नोटिस भेजा गया था। इसके 4 मिनट बाद उन्हें विदेश यात्रा न करने की सलाह दी गई। पासपोर्ट में मिली गड़बड़ियों पर जवाब देने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। सरकार ने कहा कि दास का पासपोर्ट रद्द नहीं किया गया है।

विपक्षी पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है

वह ओबीसी आरक्षण में कटौती को तैयार : पीएम मोदी

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस पर ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। संविधान निर्माता, खासकर डॉ. भीमराव आंबेडकर, इसके पूरी तरह खिलाफ थे। मोदी ने नारी शक्ति वंदन बिल का जिक्र करते हुए लिखा कि विपक्ष के एक प्रमुख दल ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाए गए विधेयक को पारित नहीं होने दिया। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि उस दल के मन में संवैधानिक मूल्यों के प्रति कितना कम सम्मान है।

पीएम बोले...नारीशक्ति को न्याय दिलाने का संकल्प नहीं रुकेगा : मोदी ने ब्लॉग में लिखा- इस साल के शुरू में जो हुआ, उसने हम सभी को शर्मसार कर दिया। संविधान की यात्रा उन महिलाओं को याद किए बिना पूरी नहीं हो सकती, जिन्होंने इसे बनाने में अहम भूमिका निभाई। पीएम ने लिखा-मैं देश की नारीशक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें न्याय दिलाने के हमारे संकल्प को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।



नक्सलवाद ने गरीबों को संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा

मोदी ने नक्सलवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा-दशकों तक देश के अनेक हिस्सों में,खासकर आदिवासी क्षेत्रों में,नक्सलियों ने बंदूक के दम पर सबसे गरीब व्यक्ति को उन अधिकारों से वंचित रखा,जो हमारे संविधान ने उसे दिए हैं। इस साल नक्सलवाद के खात्मे से मुझे विशेष संतोष मिला है।

मोदी बोले-1951 और 42 वें संविधान संशोधन से संविधान कमजोर हुआ : मोदी ने 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन और आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संशोधन का जिक्र किया। उन्होंने कहा...पहले संशोधन से नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई। उस समय अंतरिम संसद ने अपने बहुमत का इस्तेमाल कर यह संशोधन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान हुए 42 वें संशोधन ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित की और देश की संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन बदला। मोदी ने आरोप लगाया कि तब की सरकारों ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का बार-बार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल के नाम करीब 100 बार इस अनुच्छेद के इस्तेमाल का रिकॉर्ड है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 1950 के बाद पहली बार संविधान का अपडेटेड संस्करण आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। इससे संविधान आम लोगों के और करीब आया है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भी देश में अंग्रेजों के समय की दंड संहिता लागू थी।

राहुल पर बरसे गृह मंत्री शाह...कहा...कुछ लोग संविधान जेब में रखते हैं,इसकी पुस्तक लहराने से पहले पढ़ना भी जरूरी

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संविधान गौरव दिवस मनाया। इस आयोजन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा सांसद बांसुरी समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। गृह मंत्री शाह ने इस मौके पर संविधान के लिए बलिदान देने वाले सपूतों को नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग संविधान की किताब,जेब में रखते हैं। सरेआम संविधान की किताब लहराते हैं, लेकिन इसे पढ़ना भी जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद संविधान गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसका मकसद संविधान की भावना को देश के लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है और यह हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद संविधान को सिर्फ सरकार चलाने वाली किताब के तौर पर देखने की कोशिश हुई। इसके मूल विचारों और भावना को देश के किशोरों,युवाओं और आम नागरिकों तक पहुंचाने की जरूरत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इसका उद्देश्य संविधान के सर्वोच्च मूल्यों को स्कूलों,कॉलेजों और देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना था। अमित शाह ने कहा कि संविधान देश के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे तय कर सकें कि उन पर किस तरह शासन किया जाए। वहीं,सत्ता में बैठे लोगों के लिए यह जरूरी करता है कि वे संविधान की निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर सरकार चलाएं।



कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते-हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया...

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की एक नई यात्रा शुरू हुई। 1857 से 1947 तक चले 90 वर्षों के लंबे स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत बलिदान हुए। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते-हंसते मां भारती को आजाद कराने के लिए यज्ञ की वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कई लोगों ने अपना घर-बार, व्यापार, करियर, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ छोड़कर इस महान राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अथक प्रयास किए।

संविधान दिवस पर उपराष्ट्रपति ने सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में संविधान के अद्यतन संस्करण जारी किए

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में भारत के संविधान के सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में अद्यतन संस्करण जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी अनुसूचित भाषाओं में संविधान की उपलब्धता 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' की भावना को प्रतिबिंबित करती है और देश की भाषाई विविधता तथा लोकतांत्रिक समावेशिता का उत्सव है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान को नागरिकों की मातृभाषा में उपलब्ध कराने से वे अपने संवैधानिक अधिकारों,कर्तव्यों और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इससे शासन और नागरिकों के बीच दूरी कम होगी तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और मजबूत होगी। उन्होंने इस अवसर को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बताते हुए संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की जीवंत आत्मा है। उन्होंने कानून एवं न्याय मंत्रालय



के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों से संविधान को आम लोगों के और करीब लाने में मदद मिलेगी।

यह भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान भारतम और काशी तमिल संगमम जैसी पहल भारत की सभ्यतागत विरासत को सुरक्षित रखने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है। भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और पहचान की वाहक भी हैं। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं के प्रति समान सम्मान का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से विशेष लगाव होता है लेकिन दूसरों की भाषाओं और मातृभाषाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपनी मातृभाषा का उत्सव मनाने और भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यही विविधता भारत को एक सौहार्दपूर्ण राष्ट्र बनाती है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के विचारों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में भले अनेक भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन देश के विचार, आकांक्षाएं और कार्य राष्ट्र की सेवा के लिए एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में संविधान का विमोचन 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' की भावना को साकार करता है और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने सभी से 'राष्ट्र प्रथम' के मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र ही अपनी सभी भाषाओं के संरक्षण और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल,विधायी विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी करना समय की जरूरत : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उभरते जोखिमों का अंदाजा लगाने, दूसरे हालातों की जांच करने और भविष्य के सुरक्षा माहौल के लिए संस्थानों को तैयार करने की अपील की है। साथ ही बदलते जियोपॉलिटिकल हालात और युद्ध के बदलते तरीके से पैदा होने वाले खतरों का असरदार जवाब देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति,लंबी जमीनी सीमाएं,समुद्री हित और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां मुश्किल में डालती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आगे की सोच वाला नजरिया जरूरी हो गया है। नई दिल्ली में गुरुवार को 66वें नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) कोर्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टकराव के बदलते तरीके ने सुरक्षा माहौल को और भी मुश्किल बना दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पारंपरिक मिलिट्री खतरे साइबर हमलों,गलत जानकारी,आर्थिक दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और हाइब्रिड युद्ध के दूसरे तरीकों के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा और शांति और संघर्ष के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीसी रक्षा बलों, सिविल सेवाओं और दोस्त देशों के सीनियर अधिकारियों के मिलकर काम करने के अनुभव और दिमागी काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए एक कीमती प्लैटफ़ॉर्म देता है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी बनाने में सीधे योगदान देने के लिए इस दिमागी काबिलियत का ज्यादा



इस्तेमाल करने की बात कही। रक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि एनडीसी रक्षा मंत्रालय के साथ सलाह करके हर कोर्स के दौरान गहराई से जांच के लिए कुछ जरूरी आज की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की पहचान करने के लिए एक सिस्टम बनाए। उन्होंने कहा कि ये भारत के स्ट्रेटेजिक पड़ोस,बॉर्डर मैनेजमेंट,समुद्री सुरक्षा,जरूरी टेक्नोलॉजी,आर्थिक सुरक्षा,जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और बढ़ते अंदरूनी और बाहरी खतरों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने एनडीसी से एक ऐसा सिस्टम बनाने की भी अपील की,जिसके जरिए सेवारत सीनियर मिलिट्री अधिकारियों,सिविल सर्वेंट्स और दूसरी संबंधित अथॉरिटीज को देश के सामने आने वाली खास आजकल की चुनौतियों को कोर्स में हिस्सा लेने वालों के सामने औपचारिक रूप से पेश करने के लिए बुलाया जा सके।

संपादकीय

सूर्य जैसा वैभव

यह कल्पना से परे है कि कोई पंद्रह वर्षीय किशोर क्रिकेट के खेल में महज 52 गेंदों में दोहरा शतक बना दे। इतना ही नहीं,28 बॉल में शतक भी जड़ दे। साथ ही सबसे तेज 150 रन महज 40 गेंदों में बना डाले। एक पारी में 28 छक्कों का अविश्वसनीय कारनामा। यानी 204 रनों की पारी में 168 रन सिर्फ छक्कों से बटोर लिए,जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड हैं। ये कारनामा मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट के दोहा में हुए एक मैच में कर दिखाया। कहा जा रहा है कि इस टीनएजर ने क्रिकेट को वीडियो गेम बना डाला। आज दुनिया के क्रिकेट जगत में सूर्यवंशी के खेल-वैभव की चर्चा हो रही है। क्रिकेट के दिग्गज उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि उन्हें टी-20 व वन डे की भारतीय टीम में बतौर ओपनर कब जगह मिल पायेगी? उल्लेखनीय है कि वे दस इंटरनेशनल टी-20 मैचों में 185 के स्ट्राइक रेट से 295 रन बना चुके हैं। इतना ही नहीं,आईपीएल की अब तक खेली 23 पारियों में उन्होंने 228 के स्ट्राइक रेट से 1028 रन बनाये हैं। वहीं आईपीएल सीजन में भी उन्होंने क्रिस गेल जैसे दिग्गज क्रिकेटर द्वारा एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। इस किशोरवय सनसनी ने आईपीएल सीजन 2026 में 72 छक्के जड़े थे। यही वजह है कि अक्सर उनके आक्रामक खेल और छक्के मारने के कौशल की चर्चा होती है। दुनिया के अन्य देशों में उनके इस चमत्कारी हुनर की चर्चा खूब हो रही है। यहां तक कि मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा दोहा में अपना ग्रुप का मैच जीतने के बावजूद वहां सिर्फ वैभव के आतिशी खेल की चर्चा होती रही। निस्संदेह,छोटी उम्र में वैभव की कामयाबी अप्रत्याशित है। वे मौलिक खेल प्रतिभा के धनी हैं। अभी उनका लंबा क्रिकेट जीवन होना है।

यही वजह है कि वैभव की प्रतिभा और फुल फॉर्म में होने की वजह से भारतीय टीम में उनकी जगह सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। जाहिर है इस समय दुनिया के दिग्गज गेंदबाज उनके खेल को पढ़ रहे होंगे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पिचों व गेंदबाजों को उन्हें समझना होगा। जिसके लिये वैभव को अपने खेल कौशल को और समृद्ध करने की जरूरत होगी। निस्संदेह,अविश्वसनीय कामयाबी वाले वैभव के पास भविष्य में तमाम मौके आने वाले हैं। बीसीसीआई को उनको लेकर संतुलित नीति अपनाने की जरूरत होगी। कुछ लोगों का मानना है कि मौलिक व आक्रामक खेल वाले खिलाड़ी विरले ही पैदा होते हैं,लेकिन समय पर बड़े अवसर न मिलने का नकारात्मक प्रभाव उनके खेल में पड़ सकता है। क्रिकेट समीक्षक सोलह साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में मौका देने और उसके बाद उनकी अप्रत्याशित कामयाबी का जिक्र भी करते हैं। निःस्संदेह,ऐसे में विरले ही सामने आने वाली विशिष्ट प्रतिभाओं को मानसिक संबल देने की जरूरत होगी। वैभव जैसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए बेतहरीन खेल रहे हैं तो उसी अनुपात में उन्हें अच्छे अवसर भी मिलने चाहिए। आईपीएल सीजन 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल करना उनकी प्रतिभा को ही दर्शाता है।

भगवान राम संकट में आपको अपना कर्तव्य बताते हैं

श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने भगवान श्रीराम के चरणों के 5 चिह्नों ध्वज,वज्र,अंकुश,कमल और ऊर्ध्व रेखा का वर्णन किया है। वैसे अन्य पवित्र ग्रंथों को मिलाकर देखा जाए तो 48 शुभ चिह्नों की बात की गई है। दक्षिण चरण में 24 और वाम चरण में 24 शुभ चिह्न होते हैं। विशेष बात यह भी है कि जो चिह्न श्रीराम के दक्षिण चरण में हैं वे देवी सीता के वाम चरण में हैं और जो चिह्न राम जी के वाम चरण में हैं वे सीता जी के दक्षिण चरण में हैं। भगवान श्रीराम के दक्षिण चरणों के शुभ चिह्नों में ध्वजा भी है। इसका रंग लाल बताया गया है। इसे विचित्र वर्ण का कहा जाता है। इसके ध्यान से विजय तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है...



संजय गोस्वामी,
मुंबई -महाराष्ट्र

भगवान राम संकट में आपको हिम्मत देते हैं इसके पूर्व में कई उदाहरण है जो उनके प्रभु को समझा वो इतिहास में अपना नाम संकटो से घबराये नहीं हिम्मत से काम लिया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया,भगवान राम सर्व शक्तिमान हैं। धरती के एक योद्धा के रूप मे देखा जाए तो स्वयम् भगवान कृष्ण विभूति योग में बोलते हैं,'शस्त्र धारियों में मैं राम हूँ ' इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे। उतने अस्त्र शस्त्र किसी भी योद्धा के पास नहीं थे। इसकी वजह है कि एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के पास जो अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, वो उन्हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से शिक्षा में प्राप्त हुआ। परंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण अपने तपस्या के बाद किया, उन्हें भी उन्होंने भगवान राम को दिया था।

विश्वामित्र के अस्त्र शस्त्र किसी भी योद्धा के लिए दुर्लभ हैं। भगवान परशुराम भी भगवान राम को सर्व श्रेष्ठ ठहराकर विष्णु धनुष देकर जाते हैं।भगवान राम के चरण (पैर) को हिंदू ध र्में बहुत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। उनके चरण, विशेष रूप से उनके चरण चिन्ह,भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक,हैभृकुटि विला सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परहिं को सोई।।अर्थात श्रीराम के भौंह उठाने भर से सृष्टि में प्रलय हो सकती है,उनके ऊपर सपने में भी संकट नहीं आ सकता। (अरण्य कांड)शिव जी पार्वती जी से कहते हैं-उमा काल मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा।हे उमा! जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है,वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं (लंका कांड)लव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचहि जासु अनुशासित माया।।अर्थात- पलक झपकते ही श्रीराम की आज्ञा से माया अनेकों ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम है। (बाल कांड)खर दूषन त्रिसरा अरु बालि। बधे सकल अतुलित बलशाली। पापिहु जाकर नाम सुमिरहिं। अति अपार भवसागर तरहिं।।इस तरह हम देखते हैं कि श्रीराम पूर्ण परमात्मा हैं, उनके सामर्थ्य का पता लगाना मनुष्यों के वश का नहीं है।

शुभ चिह्नों में चरण में वज्र का निशान भी होता है, इसका रंग बिजली जैसा होता है। इसे इंद्र का वज्र माना जाता है। जो लोग इसका ध्यान करते हैं, उनके पापों का क्षय होता है तथा बल की प्राप्ति होती है। अंकुश का रंग श्याम है। जो व्यक्ति इसका ध्यान करता है, उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है।भगवान श्री राम के भक़्त हनुमान जी और तुलसीदास जी थे एक बार अकबर ने राम के नाम का प्रचार प्रसार क़ो देखकर इतना गुस्सा हो गया कि तुलसीदास क़ो महल में बुलाया और सर ना झुकाने पर उसे बंदी बना लिया तब हनुमान जी की बानर सेना ने धावा बोल दिया और महल में उत्पाद मचाने लगे तब अकबर क़ो समझ आया कि तुलसीदास के पास भगवान राम साथ रहते हैं और छोड़ दिया इतिहास में दर्ज है अकबर की दयालुता थी क्रूरता ये महाराणा प्रताप ने बता दिया हल्दीघाटी में युद्ध कर दिखा दिया,एक सेब बाहर से दिखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर से सड़ा हो तो लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और ठगा ठगा महसूस करते हैं अकबर दरअसल सभी हिन्दू राजा क़ो दास बनाना एक बार राणा प्रताप तुलसीदास से मिले और राम भक्त बन गए और वही अकबर ने उसे अपनी दसिता मेवाड़ के राजा के रूप में उसके साथ ना मिलने पर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ अतः अकबर ने मेवाड़ के राजा राणा प्रताप क़ो बहुत कोशिश की उनकी दासता क़ो स्वीकार करें और राजपूत मुगलों से एक रिश्ता बन सके लेकिन वो इसी सिलसिले में राणा प्रताप तुलसीदासजी के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं और राजा मान सिंह का दबाब बताते हैं तभी तुलसीदास जी ने भगवान राम का साक्षात दर्शन कराया और कहा भगवान राम हर समय तुम्हे रक्षा करेंगे और तुम्हारी बहादुरी क़ो भारत के इतिहास में अमर रहेगा और उसके बाद अकबर से किसी भी प्रकार के संधि से मना कर युद्ध करने क़ो तैयार हो गए और उनके सामने थे राजा मान सिंह और मुगलों की विशाल सेना जिसे हल्दीघाटी के युद्ध से भी जाना जाता है दरअसल राजा मान सिंह, जिन्हें मिर्ज़ा राजा के नाम से जाना जाता था, अकबर के एक वरदहस्त साथी थे,और उस मंडली के सदस्य थे जिसे बादशाह नौरत्न या 'नौ रत्न' कहते थे। वे 1562 में अकबर के



दरबार में शामिल हुए,'जोधाबाई' अकबर की पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी का एक लोकप्रिय नाम है। मान सिंह उनके भतीजे थे। वे उनके भाई,राजा भगवंत दास के पुत्र थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जिस बहादुरी से लड़ा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं उन्होंने सीधा मान सिंह जो हाथी पर सवार थे उनका घोड़ा चेतक ने हाथी पर चढ़ना चाहा और घायल हो गया अतः उनके साथियों ने सलाह दि की आप यहाँ से दूर जाकर चेतक की रक्षा करें युद्ध के दौरान, चेतक घायल हो गया था,लेकिन फिर भी वह महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से दूर ले गया। चेतक ने एक 22 फुट चौड़ा नाला भी पार किया,जिसे मुगल सेना पार नहीं कर पाई थी चेतक की वीरता और वफादारी के कारण,उसे आज भी याद किया जाता है।युद्ध के बाद,चेतक की मृत्यु हो गई और उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया, जिसे चेतक समाधि के नाम से जाना जाता है। हल्दीघाटी युद्ध का भले ही क़ोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि वहाँ महाराणा प्रताप क़ो पकड़ा नहीं गया और उनके बदले किसी और ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहना था और वो शहीद हो गया लेकिन इतिहास लिखने वाले कैसे अकबर क़ो महान मानते हैं लगता है उन्हें हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी नहीं होगी और महाराणा प्रताप के बारे में समझा नहीं होगा और फ़िल्म कार भी कैसे अकबर जो क्रूर था उसक़ो महान बनाने में फ़िल्म भी बना दि क़ोई अकबर दि ग्रेट बनाया क़ोई जोधाबाई इससे आपको नहीं लगता देश के सच्चे नायक महराणा प्रताप जो भारत क़ो अकेले ही मुगलों से लोहा लिया और उस समय उसका नेतृत्व अकबर ने ही किया था दरअसल अकबर बहुत चालक था जो भगवान राम की धरती पर पूर्ण मुग़ल समाराज्य की स्थापना ब्रेन वास कर करना चाहता था इसलिए हिन्दू क़ो भ्रमित करने के लिए राजा मान सिंह से मंदिर भी बनवाएं और इस तरह धन का लालच देकर सबको अपना गुलाम बना लिया इससे भारत क़ो केवल अपने पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं भारत क़ो राम का कर्मभूमि समझ कर देशहित में निर्णय लेना चाहिए।

संविधान की प्रस्तावना से जनपीड़ा तक फैला एक जीवन



प्रो. आरके जैन
'अरिजीत'
बड़वानी (मप्र)

किसी विचारवान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं होती कि उसने अपने जीवन में कितने पद हासिल किए, बल्कि यह होती है कि उसके रहते समाज ने कितनी बार अपने विवेक की आवाज सुनी। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक और बौद्धिक जीवन में ऐसी ही एक निर्भीक आवाज का अवसान हो गया। 26 नवंबर,संविधान दिवस की सुबह,जब देश संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्मरण कर रहा था,उसी दिन प्रख्यात गांधीवादी चिंतक,संविधान विशेषज्ञ,वरिष्ठ अधिवक्ता और सशक्त लेखक कनक तिवारी जी ने अंतिम विदाई ली। यह संयोग जितना मार्मिक है,उतना ही अर्थपूर्ण भी। जिस संविधान की आत्मा को समझने,समझाने और जनजीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया,उसी संविधान के दिवस पर उनका महाप्रयाण होना एक युगीन विडंबना की तरह हमारे सामने है। उनका जाना केवल छत्तीसगढ़ की क्षति नहीं,बल्कि उस वैचारिक परंपरा के लिए गहरा आघात है, जो सत्ता से अधिक सत्य और पद से अधिक सिद्धांतों को महत्व देती है। 26 जुलाई 1940 को जन्मे कनक तिवारी जी का जीवन बहुआयामी प्रतिभा,अथक अध्ययन और सामाजिक प्रतिबद्धता का विलक्षण उदाहरण रहा। अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में शुरुआत करने के बाद पत्रकारिता और फिर स्वर्ण पदक के साथ विधि की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अधिवक्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। मध्य प्रदेश गृह-निर्माण मंडल के अध्यक्ष से लेकर छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों तक की उनकी यात्रा उपलब्धियों से अधिक उत्तरदायित्वों की यात्रा थी। गांधी,विवेकानंद,लोहिया और भगत सिंह के विचारों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व और चिंतन में स्पष्ट दिखाई देता था। वे विचारों को केवल उद्धृत करने वाले बुद्धिजीवी नहीं थे, बल्कि उन्हें जीवन के व्यवहार और सार्वजनिक विमर्श में उतारने का साहस रखते थे। उनके लिए संविधान कानून की धाराओं का संग्रह भर नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा का जीवंत दस्तावेज था। उनकी लेखनी का मूल स्वर सत्ता की प्रशस्ति नहीं,बल्कि व्यवस्था की पड़ताल था। 'संविधान का सच','संविधान की पड़ताल', 'फिर से हिंद स्वराज' और 'गांधी और पंचायती राज' जैसी कृतियाँ उनके गहन अध्ययन, स्वतंत्र चिंतन और लोकतांत्रिक सरोकारों की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। वे संविधान को राजपथ की औपचारिकता से निकालकर जनपथ की वास्तविकता बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि संविधान की सफलता उसके उत्सवों,समारोहों और भाषणों से नहीं,बल्कि आम नागरिक के जीवन में आए न्यायपूर्ण बदलाव से मापी जानी चाहिए। आदिवासी समाज के अधिकारों,बस्तर की पीड़ा, विस्थापन,सामाजिक विषमता और वंचितों के सवालों पर उनकी मुखरता इसी संवेदनशील दृष्टि का परिणाम थी। वे उन मुद्दों पर भी बोलते थे,जिन पर बोलना सुविधाजनक नहीं होता। उनकी लेखनी में अध्ययन की प्रामाणिकता थी,तर्क की दृढ़ता थी और सबसे बढ़कर उन लोगों के प्रति संवेदना थी, जिनकी आवाज व्यवस्था तक पहुँचते-पहुँचते अक्सर दम तोड़ देती है। कनक तिवारी जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निर्भीक वैचारिक स्वतंत्रता थी। वे किसी सत्ता,सरकार अथवा राजनीतिक सुविधा के प्रति नहीं,बल्कि संविधान और जनहित के प्रति जवाबदेह रहना अपना दायित्व समझते थे। उनके लिए असहमति कोई राजनीतिक मुद्रा नहीं,लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त थी। वे जानते थे कि जिस व्यवस्था में प्रश्न पूछने वालों की आवाज कमजोर पड़ने लगे,वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती भी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए उन्होंने सत्ता के निर्णयों को तर्क और संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर परखने में कभी संकोच नहीं किया। उनकी स्पष्टवादिता में व्यक्तिगत कटुता नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन को अधिक जवाबदेह बनाने की आकांक्षा थी। वे संविधान को केवल न्यायालयों और विधि विशेषज्ञों का विषय नहीं मानते थे,उनकी दृष्टि में यह आम नागरिक के अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत और अन्याय के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का प्रभावी माध्यम था। पद, प्रतिष्ठा और विद्वता के बावजूद उनका व्यक्तित्व असाधारण सादगी और आत्मीयता से परिपूर्ण रहा। वे उन लोगों में थे,जिनकी उपस्थिति अपने पद से नहीं,विचारों के प्रभाव से महसूस की जाती है। उनकी मुस्कान में सहजता,व्यक्तित्व में विनम्रता,आँखों में अध्ययन की गहराई और वाणी में निर्भीकता थी। वे ज्ञान को प्रतिष्ठा अर्जित करने का साधन नहीं,समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का माध्यम मानते थे। आज जब सार्वजनिक जीवन में वैचारिक प्रतिबद्धता की जगह सुविधानुसार चुप्पी और सिद्धांतों की जगह पदानुकूल व्यवहार दिखाई देने लगा है, तब उनका जीवन एक महत्वपूर्ण प्रतिमान बनकर सामने आता है। उन्होंने सिखाया कि विद्वता की वास्तविक ऊँचाई इस बात से तय होती है कि व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग कितनी ईमानदारी से समाज के कमजोर और वंचित लोगों के पक्ष में करता है। संविधान दिवस पर उनका महाप्रयाण समय के माथे पर दर्ज एक असाधारण संयोग है। यह दिन हमें केवल संविधान की प्रस्तावना पढ़ने या उसके निर्माताओं को स्मरण करने का अवसर नहीं देता,बल्कि अपने लोकतांत्रिक आचरण की समीक्षा करने का दायित्व भी सौंपता है। कनक तिवारी जी का जीवन इसी समीक्षा का जीवंत उदाहरण था। वे संविधान की रक्षा को किसी एक संस्था,पद अथवा अवसर की जिम्मेदारी नहीं मानते थे। उनके लिए यह प्रत्येक जागरूक नागरिक का नैतिक कर्तव्य था। आज उनके जाने पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम संविधान को केवल सम्मान देने तक सीमित रखेंगे या उसके मूल्यों के लिए खड़े होने का साहस भी दिखाएँगे? क्या अन्याय के सामने हमारी आवाज उतनी ही मुखर होगी, जितनी समारोहों में हमारे संकल्पों की ध्वनि होती है? उनकी अनुपस्थिति इन प्रश्नों को और अधिक प्रासंगिक बना गई है। उनके परिवार,शिष्यों,मित्रों, सहकर्मियों और असंख्य प्रशंसकों के लिए यह अपूरणीय क्षति है। रायपुर की अदालतों से लेकर साहित्यिक और वैचारिक मंचों तक उनकी स्मृतियाँ लंबे समय तक अनुभव की जाती रहेंगी। लेकिन उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन केवल स्मृतियों और श्रद्धांजलियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उनकी पुस्तकें,लेख,तर्क और सार्वजनिक जीवन में व्यक्त विचार आने वाली पीढ़ियों को निरंतर यह याद दिलाते रहेंगे कि लोकतंत्र की असली ताकत सजावटी नारों में नहीं।



डॉ. विजय गर्ग
मलोट, पंजाब

शादियों के कारोबार में अब वेडिंग कोच की दस्तक

विवाह की तैयारियों से लेकर रिश्तों की समझ तक,बदल रही है शादी की दुनिया

भारतीय समाज में शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों,परंपराओं और संस्कृतियों का संगम मानी जाती है। सदियों से विवाह को एक पवित्र सामाजिक और पारिवारिक बंधन के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ शादियों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब विवाह केवल रिश्ते तय करने,रस्में निभाने और मेहमानों की मेजबानी तक सीमित नहीं रह गया है। इसके साथ एक बड़ा कारोबार विकसित हो चुका है,जिसमें वेडिंग प्लानर,इवेंट मैनेजर,डेकोरेटर,मेकअप आर्टिस्ट,फोटोग्राफर, कैटरर और फैशन डिजाइनर जैसी अनेक सेवाएं शामिल हैं। इसी बदलते परिदृश्य में अब एक नया नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है–'वेडिंग कोच'। वेडिंग कोच का काम केवल शादी को भव्य और आकर्षक बनाना नहीं है,बल्कि विवाह से जुड़े लोगों को मानसिक,भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से तैयार करना भी है। जहां वेडिंग प्लानर शादी के आयोजन, बजट, सजावट और व्यवस्थाओं पर ध्यान देता है,वहीं वेडिंग कोच दूल्हा-दुल्हन तथा उनके परिवारों को विवाह के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। वह शादी से पहले की चिंता,पारिवारिक अपेक्षाओं,आपसी संवाद,जिम्मेदारियों और नए जीवन में तालमेल बैठाने जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दे सकता है।

शादी का आयोजन या जीवन की नई शुरुआत?

आजकल शादियों में दिखावे और खर्च का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया ने इस प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। लोग चाहते हैं कि उनकी शादी दूसरों से अलग, शानदार और यादगार हो। महंगे वेडिंग डेस्टिनेशन,थीम आधारित सजावट,डिजाइनर कपड़े,प्री-वेडिंग शूट,ड्रोन फोटोग्राफी और कई दिनों तक चलने वाले समारोह आम होते जा रहे हैं। कई बार परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। शादी की तैयारियों के दौरान छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं। किस रिश्तेदार को कौन-सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन-सा समारोह किस तरह आयोजित होगा, कपड़ों और गहनों का चयन कैसा होगा तथा मेहमानों की सूची में किसे शामिल किया जाएगा–ऐसे मुद्दे तनाव का कारण बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वेडिंग कोच परिवारों को प्राथमिकताएं तय करने,अनावश्यक तनाव कम करने और आपसी संवाद बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है। उसका उद्देश्य यह समझाना है कि शादी की सफलता केवल खर्च की गई रकम या समारोह की भव्यता से नहीं, बल्कि उसमें शामिल लोगों की खुशी और संतुष्टि से तय होती है।

दूल्हा-दुल्हन की मानसिक तैयारी : विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। दो अलग-अलग परिवेश, पारिवारिक संस्कार,आदतें,विचार और अपेक्षाएं रखने वाले व्यक्ति एक नए रिश्ते में बंधते हैं। इस बदलाव के साथ उत्साह के अलावा कई प्रकार की आशंकाएं और प्रश्न भी पैदा होते हैं। क्या दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे? आर्थिक जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाएंगी? करियर और परिवार के बीच संतुलन कैसे बनेगा? दोनों परिवारों के साथ संबंध कैसे बनाए रखे जाएंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक जिम्मेदारियों में तालमेल कैसे होगा? वेडिंग कोच इन विषयों पर खुलकर बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकता है।



मोनिका डागा
'आनंद ', चेन्नई

सर्दियों की है आहट

गुलाबी सर्दियों की है आहट,
रवि की प्यारी लगे मुस्कुराहट,
मोती की लड़ियों की चटक-मटक,
परिंदों की लुभावनी सी चहक ।

पत्तों पर टिमटिमाते तुहिन कण,
खिला हुआ शांत मन का प्रागंण,
है गुणकारी सर्दियों की धूप,
सूरज की मद्धिम किरणें अनूप ।

नमी भरा मौसम शुरू हुई गलन,
ठंडी-ठंडी हवा संग ठिठुरन,
सुबह की सैर ध्यान मौन पल का,
जीवन संजीवनी सुखद कल का ।

गर्म व्यंजनों के स्वाद निराले,
मेवे काजू-बादाम मसालें,
गर्म पेय की चाहत अधिक बढ़ी,
पतीली चाय की अहर्निश चढ़ी ।

लड्डू मेथी गोंद सोंठ तिल के ,
गजक रेवड़ी खाओ हॉ जमके,
जाड़े की 'आनंद' जगमगाहट,
जादुई गीठी की गर्माहट ।

हाथ पैर छाती कान ढके हो,
इंतजाम बचाव के पक्के हो,
गुनगुने तेल की मालिश कसरत,
हष्ट-पुष्ट तन-मन की हो हसरत ।

शीतकालीन सत्र : परिसीमन-महिला आरक्षण विधेयक से सरकार की अग्निपरीक्षा



सौरभ वार्ष्णेय

संसद का आगामी सत्र देश की राजनीति के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मंत्रियों को 15 दिसंबर से पहले संसद सत्र की तैयारियां पूरी करने और सत्र से पहले विदेश यात्राओं से बचने की सलाह देना इस बात का संकेत है कि सरकार आगामी संसदीय कार्यवाही को लेकर बेहद गंभीर है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री का यह निर्देश ऐसे समय आया है,जब संसद के मानसून सत्र के स्थगित होने के 100 से अधिक दिन बाद भी उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। विपक्ष जहां संसद सत्र बुलाने में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है,वहीं सत्ता पक्ष के सामने परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियां खड़ी हैं। दरअसल,संसद का सत्र केवल विधायी कार्यवाही का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच संवाद, जवाबदेही तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मंच भी है। ऐसे में संसद की बैठक बुलाने और उसे समय पर संचालित करने को लेकर उठने वाले सवालों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। संसद की कार्यवाही में निरंतरता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है। मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हुआ था। इसके बाद से सत्रावसान नहीं होने और अगले सत्र की तारीख को लेकर अनिश्चितता ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर संसद की बैठक बुलाने में देरी कर रही है। हालांकि,सरकार के पास संसदीय कार्यक्रम निर्धारित करने का संवैधानिक और प्रक्रियागत अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसद को राजनीतिक सुविधा के अनुसार चलाने की धारणा मजबूत होने दी जाए। संसद का महत्व किसी एक दल या सरकार से बड़ा है।आगामी सत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण विधेयक माना जा रहा है। सरकार यदि इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करती है तो यह उसके लिए एक बड़ी राजनीतिक और विधायी परीक्षा होगी। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा की 543 सदस्यीय वर्तमान संरचना में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 362 सदस्यों का है,जबकि राजनीतिक चर्चाओं में 361 मतों का आंकड़ा भी सामने रखा जा रहा है। ऐसे में सरकार को अपने मौजूदा संख्याबल से आगे बढ़कर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास वर्तमान में लगभग 320 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। इस स्थिति में सरकार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना आसान नहीं होगा। केवल गठबंधन के संख्याबल के भरोसे संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना संभव नहीं दिखता। यही कारण है कि सरकार को क्षेत्रीय दलों और विपक्ष के कुछ घटकों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ सकता है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या महिला आरक्षण जैसे व्यापक सामाजिक महत्व के विषय को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठाकर देखा जाएगा? महिलाओं को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना भारतीय लोकतंत्र की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता है। लेकिन यदि इस व्यवस्था को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर लागू किया जाता है तो इसके राजनीतिक,सामाजिक और संघीय प्रभावों पर गंभीर चर्चा आवश्यक हो जाती है।

परिसीमन का मुद्दा केवल लोकसभा की सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के संघीय ढांचे, राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन से है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण,शिक्षा,स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में यदि भविष्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों का संसद में सापेक्षिक राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। यह चिंता पूरी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के मत का समान महत्व होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण संघीय देश में राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है।सरकार द्वारा लोकसभा की कुल सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के संभावित फॉर्मूले पर विचार इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने और 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हिस्सेदारी को संरक्षित रखने की संभावना पर चर्चा हो रही है। यदि ऐसा कोई फार्मूला सामने आता है तो वह दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन इस विषय पर केवल राजनीतिक आश्वासन पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि प्रस्तावित परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन किस प्रकार बना रहेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी राज्य को जनसंख्या नियंत्रण और विकास के प्रयासों की सफलता के कारण राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े। आगामी सत्र में विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी सरकार को घेर सकता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार,चार राज्यों में फैला मिला ठगी का नेटवर्क

म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम का हो रहा था लेन-देन,तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक दर्ज मिलीं ऑनलाइन शिकायतें,किसी ने पैसों के लालच में दिए दस्तावेज तो दूसरा पांच रुपये के नोट के बदले एक लाख पाने के झांसे में फंसा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों में दूसरों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम का लेन-देन करने वाले म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में दोनों आरोपियों के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधों में किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन खातों से संबंधित ऑनलाइन शिकायतें देश के कई राज्यों में दर्ज पाई गई हैं। पुलिस ने एक मामले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान तथा दूसरे मामले में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक,ओडिशा और पश्चिम बंगाल में शिकायतें दर्ज होने की जानकारी दी है। पुलिस मुख्यालय रायपुर से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर फर्जी मोबाइल नंबर जारी





करने वाले पॉइंट ऑफ सेल और म्यूल बैंक खाताधारकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत साइबर सेल से प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों की जांच में कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किए जाने का खुलासा हुआ। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। पहले मामले में एचडीएफसी बैंक खाते से संबंधित शिकायतें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के साइबर पुलिस पोर्टल पर दर्ज मिलीं।

जांच के दौरान पुलिस ने मनोहर लाल तिग्गा (25 वर्ष),पिता नाथ तिग्गा, निवासी जराकेला तुतपारा बरगीडीह, थाना लुण्ड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि वर्ष 2023 में काम की तलाश में अंबिकापुर आने के दौरान अपने एक दोस्त के माध्यम से वह एमजी रोड स्थित स्मार्ट पॉइंट के ऊपर संचालित वर्चुअल फैशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के कार्यालय पहुंचा था। वहां उसने एक फॉर्म भरकर अपनी फोटो,आधार कार्ड,कक्षा 12वीं की अंकसूची,पैन कार्ड और एचडीएफसी बैंक खाते की छायाप्रति जमा की थी। इसके लिए उसने 200 रुपये शुल्क भी दिया था। जांच में सामने आया कि उसके बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अधिक पैसे के लालच में अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया था। इस मामले में अपराध क्रमांक 825/2026 के तहत धारा 420 भादवि में अपराध दर्ज किया गया था। दूसरे मामले में पुलिस ने विकास लकड़ा (40 वर्ष),पिता सुरेश लकड़ा, निवासी लक्ष्मीपुर तेंदूपारा, अंबिकापुर,थाना मणिपुर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में संबंधित बैंक खातों के विरुद्ध आंध्रप्रदेश,कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज मिली थीं। पुलिस के अनुसार आरोपी जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान फेसबुक पर पांच रुपये के ट्रैक्टर छाप नोट के बदले एक लाख रुपये मिलने का विज्ञापन देखकर झांसे में आ गया था।

इसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को आरबीआई का अधिकारी बताया और उसे बैंक खाते खुलवाने के लिए कहा। आरोपी ने उक्त व्यक्ति के कहने पर अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक और सितंबर 2024 में केनरा बैंक में खाते खुलवाए। दोनों खातों में संबंधित अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर दर्ज कराए गए। इतना ही नहीं,खाते के सत्यापन के नाम पर दोनों बैंकों के एटीएम कार्ड भी कूरियर के माध्यम से राजस्थान के भिवाड़ी स्थित पते पर भेज दिए। कुछ समय बाद जब संबंधित व्यक्ति से संपर्क टूट गया,तब आरोपी ने अपने बैंक खातों में अपना मोबाइल नंबर दोबारा जुड़वाया। पुलिस जांच में इन खातों का इस्तेमाल भी साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में किए जाने की जानकारी सामने आई। विवेचना के दौरान आरोपी के कब्जे से पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक की पासबुक ई-साक्ष्य के रूप में जब्त की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 626/2026 के तहत धारा 318(4) बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों मामलों में पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अब इन बैंक खातों के माध्यम से हुए लेन-देन, ठगी की रकम और खातों का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

लालच में बैंक खाता देना पड़ सकता है भारी

साइबर अपराधी अक्सर सीधे लोगों के खातों में ठगी की रकम मंगाने के बजाय दूसरे व्यक्तियों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे नौकरी, कमीशन, अतिरिक्त कमाई या किसी आकर्षक योजना का लालच देते हैं। कई बार फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है। ऐसे बैंक खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। खाताधारक भले ही ठगी की पूरी साजिश में शामिल न हो,लेकिन अपने खाते और बैंकिंग दस्तावेज उपलब्ध कराने पर वह भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। सरगुजा पुलिस ने ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। दोनों मामलों की कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश सिंह,साइबर सेल प्रभारी अजीत मिश्रा,उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह,प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी,प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा तथा आरक्षक हरिनाम सिंह, अनुग्रस लकड़ा, प्रवीण खलखो, राजीव एक्का और बिजेंद्र पैकरा की भूमिका रही।

राघवपुरी वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

सरगुजा में 15 दिनों तक दूरस्थ गांवों में चलेगा जागरूकता अभियान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा की ओर से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में राघवपुरी वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर बुजुर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं, अब मोबाइल ई-सेवा वैन के माध्यम से जिले के दूरस्थ गांवों तक विधिक सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। 25 नवंबर को आयोजित शिविर में न्यायाधीश कृष्णपाल सिंह भदौरिया और स्मिता रतनावत ने वृद्धजनों को उनके विधिक अधिकारों,निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा नालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बुजुर्गों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी कानूनी समस्या पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर विकास सिंह भी उपस्थित रहे। इसमें 13 पुरुष और 5 महिलाओं सहित कुल 18 लोग शामिल हुए।

15 दिनों तक गांवों में चलेगा मोबाइल ई-सेवा वैन का अभियान : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी और केंद्रीय न्याय विभाग की संयुक्त पहल के तहत मोबाइल ई-सेवा वैन 26 नवंबर को सरगुजा पहुंची। इस वैन के माध्यम से जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 15 दिनों तक



विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत पहले दिन ग्राम सलवा से की गई। मोबाइल ई-सेवा वैन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस है। इसके माध्यम से नागरिक अपने न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति और अगली पेशी की तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही ई-कोर्ट सेवाओं के उपयोग में भी सहायता मिलेगी।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मिलेगी कानूनी जानकारी : अभियान के दौरान ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से विवादों के समाधान की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं,बच्चों,वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कानूनी संरक्षण एवं सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक कानूनी सहायता पहुंचाना है, जहां के लोगों के लिए न्यायालयीन सेवाओं तक पहुंचना कठिन होता है। मोबाइल वैन के जरिए लोगों को उनके गांव में ही कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

चार दिन में 9.8 डिग्री लुढ़का पारा,सरगुजा में बढ़ी ठिठुरन

न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री पर पहुंचा,अगले दो-तीन दिन और बढ़ेगी ठंड; खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले युवक की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

चक्रवात अकवान का असर खत्म होते ही सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पडऩी शुरू हो गई है। उत्तरी सर्द हवाओं के प्रवेश से पिछले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दोपहर में भी ठिठुरन महसूस की गई और लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम विभाग ने आगामी दो से तीन दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। दरअसल,कुछ दिन पहले चक्रवात अकवान के प्रभाव से बारिश हुई थी। इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 22 नवंबर को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस था। मौसम साफ होने और उत्तरी सर्द हवाएं चलने के साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट आई और गुरुवार को यह 9.2 डिग्री पर पहुंच गया। सरगुजा जिले के मैनपाट और बलरामपुर जिले के सामरीपाट क्षेत्र में ठंड का असर और



अधिक है। यहां मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा ठिठुरन महसूस की जा रही है।

अगले दो-तीन दिन और बढ़ेगी ठंड : मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी सर्द हवाओं का प्रवेश लगातार जारी है। इसके चलते आगामी दो से तीन दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है।

गांधी स्टेडियम के पास खुले में पड़े युवक की मौत : बढ़ती ठंड के बीच शहर के गांधी स्टेडियम के पास गुरुवार सुबह एक युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि करीब 35 वर्षीय युवक बुधवार रात खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। गुरुवार सुबह वह प्लास्टिक में चावल लेकर आया और खाने लगा। इसी दौरान अचानक लुढ़क गया और उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर गर्म कपड़े भी नहीं थे। आशंका जताई जा रही है कि पूरी रात ठंड में खुले में पड़े रहने के कारण उसकी मौत हुई होगी। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

चौक-चौराहों पर अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं

शहर में कड़ाके की ठंड के बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से अब तक चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गांधी चौक और प्रतीक्षा बस स्टैंड जैसे स्थानों पर रातभर लोगों की आवाजाही रहती है। यहां यात्रियों, राहगीरों और जरूरतमंदों को ठंड से राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था जरूरी है। रात गुजारने वाले बेसहारा लोगों के लिए ठंड से बचाव के इंतजाम किए जाने चाहिए।

संविधान दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय संविधान के प्रति सम्मान एवं उसमें निहित संवैधानिक मूल्यों, आदर्शों तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के उद्देश्य से आज संविधान दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान में निहित मूल आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रभारी कुलसचिव श्री प्रवीण अग्रवाल एवं सहायक कुलसचिव श्री टेमन लाल देवांगन सहित विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थितजनों ने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक कर्तव्यों तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। विश्वविद्यालय परिवार ने संविधान दिवस के इस अवसर पर संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने तथा उनके अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।



स्कूल-कॉलेजों की सुरक्षा पर पुलिस सख्त,संचालकों को दिए कड़े निर्देश....

प्रवेश द्वार से हॉस्टल तक सीसीटीवी की निगरानी अनिवार्य,छात्र-छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं,संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल पुलिस को सूचना देने कहा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस ने गंभीरता दिखाई है। स्कूल-कॉलेज परिसरों में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने और विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों-कॉलेजों के संस्था प्रमुखों और संचालकों की बैठक ली गई। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने संस्थानों के प्रवेश द्वार, गलियारों और संवेदनशील स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने





को कहा। स्पष्ट किया गया कि कैमरे केवल लगाने तक सीमित न रहें,बल्कि हर समय चालू हालत में होने चाहिए। वहीं, छात्रावासों में बालक और बालिका विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग सुरक्षा व्यवस्था तथा पर्याप्त दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और आपातकालीन सहायता को भी सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बताया गया। किसी छात्र-छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर तत्काल प्राथमिक उपचार और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ अभिभावकों को सूचना देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि संस्थान परिसर अथवा आसपास किसी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की आशंका होने पर सूचना देने में देरी न की जाए। त्वरित पुलिस सहायता के लिए राजपत्रित अधिकारियों के संपर्क नंबर भी संस्था प्रमुखों को उपलब्ध कराए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन,नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक बी.,एसडीएम वन सिंह नेताम, जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा,डीएसपी डी.के. सिंह सहित विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के संस्था प्रमुख एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

फर्जी राजस्व आदेश के सहारे लाखों की जमीन हथियाने की कोशिश,एक आरोपी गिरफ्तार

राजस्व मंडल बिलासपुर के 2019 के आदेश में की गई थी कूटरचना,तीन खसरों की जमीन अपने नाम कराने 2023 में दिया था आवेदन,दूसरा आरोपी फरार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जमीन संबंधी मामलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने का एक मामला सरगुजा जिले के लुण्ड्रा क्षेत्र में सामने आया है। यहां राजस्व मंडल बिलासपुर के पुराने आदेश की कूटरचना कर उसके आधार पर दूसरे की भूमि अपने नाम कराने का प्रयास किया गया। मामले की जांच के बाद लुण्ड्रा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर राजस्व मंडल बिलासपुर के कथित फर्जी आदेश



की सत्यापित प्रति भी जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,इस मामले की शिकायत तुषार मानिक,नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय लुण्ड्रा ने लिखित आवेदन के माध्यम से दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि अनुविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय धौरपुर में प्रस्तुत एक राजस्व प्रकरण के दौरान ग्राम खाराकोना निवासी मुस्लिम पिता स्व. मोहिउद्दीन और उसके एक साथी द्वारा राजस्व मंडल बिलासपुर के आदेश की कूटरचित प्रति प्रस्तुत की गई थी। आरोपियों ने इस दस्तावेज को वास्तविक आदेश बताकर ग्राम खाराकोना स्थित भूमि को अपने नाम कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। मामला खसरा नंबर 814/1, 814/3 और 814/4 से संबंधित है, जिनका रकबा क्रमशः 2.40 हेक्टेयर, 0.113 हेक्टेयर और 0.433 हेक्टेयर बताया गया है। आरोपियों द्वारा इन भूमियों के संबंध में राजस्व मंडल बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक रू16/क्र07/2019 में पारित दिनांक 1 जून 2019 के आदेश को आधार बनाया गया था। इसी कथित आदेश की कूटरचित प्रति को असली दस्तावेज बताकर 11 दिसंबर 2023 को भूमि अपने नाम कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, विभागीय जांच में प्रस्तुत आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया। शिकायत के आधार पर थाना लुण्ड्रा में अपराध क्रमांक 283/2026 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस के अनुसार, जांच में आरोपी और उसके साथी की संलिप्तता सामने आने के बाद ग्राम खाराकोना निवासी मो. मुस्लिम फिरदौसी (55 वर्ष), पिता स्व. मोहिउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर राजस्व मंडल बिलासपुर के कथित फर्जी आदेश की सत्यापित प्रति भी बरामद कर जब्त की गई। उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

संविधान दिवस के अवसर पर कमिश्नर कार्यालय में सहित शासकीय कार्यालयों में हुआ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन

राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने ली गई शपथ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

संविधान दिवस के अवसर पर आज गुरूवार 26 नवंबर को सरगुजा संभागायुक्त कार्यालय अम्बिकापुर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) का सामूहिक वाचन किया गया। कमिश्नर श्री नरेन्द्र दुग्गा ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपायुक्त राजस्व श्रीमती शारदा अग्रवाल,उपायुक्त (विकास) श्री आर.के खुंटे सहित



कमिश्नर कार्यालय के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। संविधान दिवस के अवसर पर गुरूवार को सरगुजा संभाग के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में विभाग प्रमुखों और अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा भी संविधान की प्रस्तावना का पठन और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली गई।

CMYK



सुबह घर से निकली किशोरी नहीं लौटी,अपहरण की आशंका पर मामला दर्ज

डिम्पल की तलाश में पुलिस ने झोंकी ताकत,सुराग देने वाले को मिलेगा नकद पुरस्कार

ग्राम रामगढ़ की 16 वर्षीय कुमारी डिम्पल सुबह टहलने निकली थी...फिर नहीं लौटी

-संवाददाता-
सोनहत (कोरिया),26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ से 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है,किशोरी रोज की तरह सुबह टहलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वापस नहीं लौटी,परिजनों ने पहले आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की,लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली,किशोरी का सुराग नहीं मिलने पर मामला पुलिस तक पहुंचा, नाबालिग को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका के आधार पर थाना सोनहत में अपराध क्रमांक 115/2026, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज दीपक झा ने 25 नवंबर 2026 को सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की है,इसमें लापता किशोरी की पतासाजी और अज्ञात आरोपी को पकड़वाने में मददगार महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति को 30 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है,पुलिस ने सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखने की बात भी कही है,अब पुलिस की अपील है कि यदि किसी व्यक्ति को किशोरी के संबंध में कोई जानकारी मिलती है,तो वह तत्काल संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करे।

सुबह घर से निकली डिम्पल,फिर नहीं लौटी-पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से जारी उद्घोषणा के अनुसार लापता किशोरी की पहचान कुमारी डिम्पल,पिता रामाधार केवट, उम्र 16 वर्ष, निवासी ग्राम रामगढ़,चौकी रामगढ़,थाना सोनहत,जिला कोरिया के रूप में की गई है,वह रोज की भांति सुबह टहलने के लिए घर से निकली थी,इसके बाद वह वापस नहीं लौटी,किशोरी के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों और रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की। संभावित स्थानों पर पता लगाने के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला,तो परिजन चिंतित हो उठे। मामले में अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की।

अपहरण की आशंका पर सोनहत थाने में अपराध दर्ज-पुलिस उद्घोषणा में उल्लेख किया गया है कि नाबालिग बालिका को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका के आधार पर थाना सोनहत में अपराध क्रमांक 115/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है,पुलिस द्वारा किशोरी की तलाश और अज्ञात आरोपी की पतासाजी के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उद्घोषणा जारी होने तक किशोरी और संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी,पुलिस ने इस मामले में आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है,किसी व्यक्ति को किशोरी के बारे में जानकारी हो,उसने कहीं उसे देखा हो या उसके आने-जाने के संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुराग मिला हो, तो वह बिना देरी किए पुलिस को सूचना दे सकता है। पुलिस ने जारी किया किशोरी का हुलिया-लापता किशोरी की पहचान और तलाश में आम लोगों की सहायता लेने के लिए पुलिस ने उसका शारीरिक हुलिया भी सार्वजनिक किया है।

- नामः कुमारी डिम्पल
- पिता का नामः रामाधार केवट
- उम्रः 16 वर्ष
- निवासः ग्राम रामगढ़, चौकी रामगढ़, थाना सोनहत, जिला कोरिया
- चेहराः गोल
- रंगः गोरा
- कदः लगभग 4 फीट 5 इंच
- बालः सीधे
- घटना के समय पहनावाः नीले रंग का लॉन्ग फ्रॉक और नीला-हरा रंग का दुपट्टा

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस हुलिए से मिलती-जुलती किशोरी दिखाई देने पर स्वयं किसी प्रकार का जोखिम उठाने के बजाय तत्काल पुलिस को जानकारी दें।

सूचना देने वाले को मिलेगा 30 हजार रुपये का नकद पुरस्कार

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा द्वारा जारी उद्घोषणा में स्पष्ट किया गया है कि लापता किशोरी की बरामदगी और अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में मददगार साबित होने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले व्यक्ति को 30,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा,सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा, पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज का होगा,यह पुरस्कार घोषणा इस बात को दर्शाती है कि पुलिस अब किशोरी की तलाश में आम नागरिकों से भी सहयोग चाहती है,ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति को किशोरी के संबंध में कोई जानकारी मिलती है,तो वह पुलिस तक पहुंचाकर उसकी सुरक्षित बरामदगी में मदद कर सकता है।

सुरक्षित बरामदगी के लिए जनसहयोग जरूरी

16 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला परिवार के लिए गंभीर चिंता का विषय है,ऐसे मामलों में समय पर मिलने वाली छोटी-सी जानकारी भी तलाश की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है,पुलिस ने किशोरी की पतासाजी और अज्ञात आरोपी तक पहुंचने के लिए आम नागरिकों से सहयोग मांगा है, फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता किशोरी की सुरक्षित बरामदगी है,पुलिस की सार्वजनिक उद्घोषणा के बाद अब क्षेत्र के लोगों से भी अपेक्षा है कि वे जारी हुलिए और विवरण पर ध्यान दें तथा कोई भी विश्वसनीय जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, सवाल केवल एक लापता किशोरी को खोजने का नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाने का है।

खेल के मैदान में दिखा युवा जोश और प्रतिभा का शानदार संगम,फुटबॉल खिलाड़ियों ने बांधा समां

खेल प्रतिभाओं को नई पहचान देने के साथ एकता,अनुशासन और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाती हैं खेल प्रतियोगिताएं : मंत्री राजेश अग्रवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल आज सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन,उत्साह एवं सामूहिक खेल भावना से मैदान में रोमांच भर दिया। मंत्री श्री अग्रवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी प्रतिभागियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का



सशक्त माध्यम हैं। खेल न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष करने की भावना भी विकसित करते हैं। खेल के मैदान में अर्जित अनुभव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि फुटबॉल जैसे सामूहिक खेल आपसी सहयोग,समन्वय,एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। युवाओं को अपनी मेहनत,लगन और समर्पण के बल पर खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरगुजा अंचल में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन उभरती खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल,आपसी तालमेल और खेल भावना का परिचय दिया। खिलाड़ियों के जोश, उत्साह और उत्कृष्ट प्रदर्शन से खेल मैदान का वातावरण रोमांचक बना रहा। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ ही आपसी सहयोग, अनुशासन,एकता और सद्भाव का संदेश दिया। मंत्री श्री अग्रवाल ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों,आयोजकों एवं सहयोगकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर विद्यार्थियों को दूध और पोषण का महत्व बताया

जवाहर नवोदय विद्यालय में देवभोग दुग्ध संयंत्र ने आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (देवभोग) के दुग्ध संयंत्र अंबिकापुर की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करीब 460 विद्यार्थियों और 30 शिक्षकों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को दूध और दुग्ध उत्पादों के पोषण संबंधी महत्व की जानकारी देने के साथ देवभोग के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य राजू दुबे, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. रूपेश कुमार, डॉ. अमित सिंह, डॉ. आशीष महंत और दुग्ध संयंत्र अंबिकापुर के प्रभारी विमल पटेल उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के महत्व और श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन के भारतीय डेयरी क्षेत्र में योगदान के बारे में बताया गया। वक्ताओं ने दैनिक जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों की उपयोगिता, संतुलित आहार तथा बेहतर पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में देवभोग के फ्लेवर्ड मिल्क, रबड़ी और श्रीखंड सहित विभिन्न उत्पादों का परिचय कराया गया। विद्यार्थियों को इन उत्पादों का स्वाद भी चखाया गया और उनकी गुणवत्ता व विशेषताओं की जानकारी दी गई। आयोजकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में पोषण, स्वस्थ जीवनशैली और सहकारी डेयरी आंदोलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।



कुसुवामुड़ा-सुखरी भंडार में कबरा हाथी के दल का डेरा, कई गांवों में अलर्ट

बस्ती के करीब पहुंचे कबरा समेत दो हाथियों को वन अमले ने आधी रात को खदेड़ा



-संवाददाता-
उदयपुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में कबरा हाथी और उसके दल की हलचल लगातार बनी हुई है। बुधवार रात सुखरी भंडार गौठान के पास 16 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। इसी दौरान कबरा हाथी समेत दो हाथी मुख्य दल से अलग होकर गन्ने की बाड़ी से निकलकर बस्ती की ओर बढ़ने लगे। हाथियों के आबादी क्षेत्र के करीब पहुंचने से वन विभाग का अमला अलर्ट हो गया। वनकर्मियों को दोनों हाथियों को बस्ती से दूर खदेड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आधी रात के बाद उन्हें आबादी क्षेत्र से दूर करने में सफलता मिली। वन विभाग के अनुसार वर्तमान में कबरा हाथी सहित कुल 18 हाथी कुसुवामुड़ा और बिच्छलघाटी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। इनमें 17 हाथियों का दल और कबरा हाथी शामिल है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के गांवों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

इन गांवों में आवाजाही की आशंका : हाथियों की संभावित आवाजाही को देखते हुए सत्तीमुड़ा,सायर,पंडो कॉलोनी,सानी बर्रा,सुखरी भंडार, बिच्छलघाटी,लक्ष्मणगढ़ सहित आसपास के गांवों में ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा गया है।

वन विभाग ने ग्रामीणों से हाथियों के पीछे नहीं जाने, उनके करीब जाकर फोटो-वीडियो नहीं बनाने और उन्हें घेरने या भगाने की कोशिश नहीं करने की अपील की है। रात में खेतों और जंगल की ओर जाने से बचने तथा हाथियों की गतिविधियों की सूचना तत्काल वन विभाग को देने कहा गया है।

ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर सूरजपुर पुलिस अलर्ट,दुकानों में पहुंचकर सीसीटीव्ही कैमरे एवं सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण

-संवाददाता-
सूरजपुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिले में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने जिले के समस्त थाना-चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र की ज्वेलरी दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच करने के निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के परिपालन में दिनांक 25.11.2026 को जिले के विभिन्न थाना-चौकी के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने क्षेत्र की ज्वेलरी दुकानों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, इस दौरान दुकानों में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सीसीटीव्ही कैमरों की स्थिति, उनकी कार्यशीलता तथा रिकॉर्डिंग के लिए उपलब्ध बैकअप स्टोरेज की जांच की गई, पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देशित किया कि दुकान के अंदर एवं बाहर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि दुकान के प्रवेश एवं निकास द्वार सहित आसपास की गतिविधियों पर भी सतत निगरानी रखी जा सके।

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै चम्पा श्याम (पुराना नाम जिसे बदला जाना है) पत्नी स्व0 ललन सिंह गॉव ईरगवॉ तहसील लखनपुर जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ ने अपना नाम चम्पा श्याम (पुराना नाम) से बदल कर चम्पा बाई (नया नाम) रख लिया है।

सपथकर्ता
चम्पा श्याम
गॉव ईरगवॉ तहसील लखनपुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मेराज आ0 मो. मिन्हाज, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 801, नवागढ़, थाना व तहसील - अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) का एतद् द्वारा मैं पूष्टि करता हूँ यह कि मेरा वास्तविक नाम मेराज (MERAJ) है, जो मेरे कक्षा-10वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है।

मेरे आधार कार्ड क्र. 7669 4787 2881 में मेरा नाम त्रुटिवश मो मैराज (MO MAIRAJ) दर्ज कर दिया गया है, जो गलत हैं, जिसे मैं बदलकर मेरा सही नाम मेराज (MERAJ) करना चाहता हूँ, इसी नाम से मुझे जाना एवं पहचाना जावे, जिस हेतु मैं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सपथकर्ता
मेराज

नाम परिवर्तन सूचना

मैं आइफापरवीन (IFAPARVEEN) (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/पुत्री - महबूब आलम (MAHBOOB ALAM) निवासी मकान न0 03 पटेल पारा, कान्तिप्रकाशपुर, जिला-सरगुजा की स्थायी निवासी हूँ। मेरे पुराना नाम आइफापरवीन (IFA-PARVEEN) है और मैं अपना नाम बदलकर आईफा परवीन (IFA-PARVEEN) (नया नाम) करवाना चाहता हूँ।

मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है। मैं नाम बदलकर, यदि कोई गैर कानूनी काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सपथकर्ता
आइफापरवीन

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ- 20(3) /2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक श्रीमती आरती सिंह पति विनोद सिंह, निवासी बौरीपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग के द्वारा शीट नम्बर -03 मोहल्ला- कंपनी बाजार, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1358/1. 1358/2, 1358/3, 1358/6, 1359/1 रकबा 0.02, 0.01/4, 0.001/2, 0.001/2, 0.02 एकड़ भूमि को बैंक में बंधक रखने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.12.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 25.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में आवेदक अनिता सरकार आ. भावेन सरदार व अन्य निवासी ग्राम सुभाषनगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 212/4 रकबा 0.160 हे. भूमि के नक्शा में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि शक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 11/12/2026 के पूर्व स्वय अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-28/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से भारी ।

सील
तहसीदार
अंबिकापुर,सरगुजा



नगर पालिका के चक्कर होंगे कम,मोबाइल से मिलेंगी सेवाएं! प्रशांत गुप्ता का डिजिटल बैकुंठपुर मॉडल...

ऑनलाइन शिकायत से बजट की पारदर्शिता तक,सीए प्रशांत ने रखा स्मार्ट नगर पालिका का विजन

कागजी प्रक्रिया से डिजिटल व्यवस्था की ओर बैकुंठपुर,प्रशांत गुप्ता ने गिनाईं सात प्रमुख सुविधाएं

जन्म प्रमाणपत्र से भवन निर्माण अनुमति तक ऑनलाइन सुविधाओं की परिकल्पना, शिकायत,टैंडर,बजट और सामुदायिक भवन की बुकिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,26 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

नगर पालिका चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता के बीच भाजपा से दावेदारी कर रहे सीए प्रशांत गुप्ता ने बैकुंठपुर के विकास को लेकर अपना अलग विजन सार्वजनिक किया है, उनका जोर शहर में नए भवनों और भौतिक निर्माण कार्यों के साथ नगर पालिका की कार्यप्रणाली को तकनीक आधारित बनाने पर है, उन्होंने वीडियो के माध्यम से डिजिटल बैकुंठपुर की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भविष्य में नगर पालिका की सेवाएं नागरिकों के मोबाइल तक पहुंचाई जा सकती हैं। प्रशांत गुप्ता के प्रस्ताव का मुख्य आधार एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से नागरिक नगर पालिका से जुड़ी सेवाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकें, शिकायत दर्ज कर सकें और अपने आवेदन की पूरी स्थिति देख सकें,उनकी योजना में जन्म प्रमाणपत्र, भवन निर्माण अनुमति,पशुओं से संबंधित सहायता एवं सूचना,सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग,टेंडर और निविदाओं की जानकारी,नागरिक सुझाव तथा नगर पालिका बजट की पारदर्शिता जैसे विषय शामिल हैं, बैकुंठपुर में कांग्रेस की ओर से आशीष यादव उर्फ लाला का 13 सूत्रीय संकल्प पत्र सामने आने के बीच प्रशांत गुप्ता का डिजिटल विजन चुनावी चर्चा में एक अलग मुद्दा जोड़ता है,जहां एक ओर शहर की भौतिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर संकल्प पत्र जारी किया गया है,वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है,हालांकि,प्रशांत गुप्ता का डिजिटल मॉडल फिलहाल एक प्रस्तावित विजन है,इसे नगर पालिका में लागू हो चुकी व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसके लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म,बजट,डाटा सुरक्षा,कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विभागीय समन्वय जैसी व्यवस्थाएं तैयार करनी होंगी।

क्या होगी डिजिटल बैकुंठपुर की परिकल्पना?- प्रशांत गुप्ता के प्रस्ताव के अनुसार, नगर पालिका की सेवाओं के लिए एक डिजिटल पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप तैयार किया जा सकता है,इसका उद्देश्य नागरिकों को आवेदन,शिकायत और जानकारी के लिए बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत कम करना है।

4. टेंडर एवं निविदाओं की जानकारी सार्वजनिक- चौथे सेवा क्षेत्र में नगर पालिका के टेंडर और निविदाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने की बात है, इससे इच्छुक ठेकेदारों और नागरिकों को संबंधित सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल सकती हैं, यदि निविदाओं के प्रकाशन, आवेदन की अंतिम तारीख, तकनीकी शर्तों और प्रक्रिया की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होती है, तो पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है, इसके लिए सूचना को नियमित रूप से अपडेट करना आवश्यक होगा।

5. नागरिक सुझाव और शिकायत दर्ज करने की सुविधा- पांचवें सेवा क्षेत्र में नागरिकों को अपने सुझाव और समस्याएं ऑनलाइन भेजने की सुविधा देने की परिकल्पना है, नागरिक अपने मोबाइल से आवेदन अथवा सुझाव दर्ज कर सकेंगे और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, यह व्यवस्था तभी कारगर होगी जब हर शिकायत को एक अलग पहचान संख्या मिले, उसे संबंधित अधिकारी तक भेजा जाए और उसके समाधान की स्थिति नियमित रूप से अपडेट की जाए।

6. नगर पालिका बजट और वित्तीय पारदर्शिता- छठे सेवा क्षेत्र में नगर पालिका के बजट और उससे संबंधित जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की बात कही गई है, इससे नागरिकों को यह समझने का अवसर मिल सकता है कि नगर पालिका में किन मदों पर राशि खर्च की जा रही है और विकास कार्यों के लिए क्या प्रावधान हैं, बजट संबंधी जानकारी को सरल भाषा में उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि आम नागरिक उसे आसानी से समझ सकें।

7. आवेदन की पूरी डिजिटल यात्रा और ऑनलाइन निगरानी- सातवें सेवा क्षेत्र के रूप में आवेदन की शुरुआत से लेकर अंतिम निपटारे तक की पूरी डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध कराने की परिकल्पना है, यानी नागरिक आवेदन जमा करने के बाद यह देख सकेगा कि वह किस अधिकारी अथवा विभाग के पास पहुंचा है, उसकी जांच किस स्थिति में है और निर्णय कब लिया गया, यह व्यवस्था नगर पालिका में जवाबदेही बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है, इसके लिए प्रत्येक विभाग के लिए समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित करना आवश्यक होगा।

1. जन्म प्रमाण-पत्र और भवन निर्माण अनुमति की ऑनलाइन सुविधा

पहले सेवा क्षेत्र में जन्म प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन और भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया को डिजिटल करने की बात है,भवन निर्माण अनुमति के मामले में आवेदन की स्थिति, जांच की प्रगति और आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने की परिकल्पना है,इससे नागरिकों को यह जानने में सुविधा मिल सकती है कि उनका आवेदन किस स्तर पर लंबित है और आगे किस प्रक्रिया की जरूरत है,हालांकि अंतिम स्वीकृति संबंधित नियमों और सक्षम अधिकारियों की जांच के आधार पर ही होगी।

2. पशुओं से संबंधित सहायता एवं सूचना

दूसरे सेवा क्षेत्र में पशुओं से जुड़ी सहायता और सूचना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की बात कही गई है, इससे नागरिक पशुओं से संबंधित समस्या या सहायता की जरूरत की जानकारी ऑनलाइन दे सकेंगे, इस व्यवस्था का व्यावहारिक लाभ तभी होगा जब शिकायत या सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग अथवा जिम्मेदार टीम को समय पर कार्रवाई के लिए जोड़ा जाए।

3. सामुदायिक भवन और अन्य बुकिंग ऑनलाइन

तीसरे सेवा क्षेत्र में सामुदायिक भवन की बुकिंग सहित नगर पालिका से जुड़ी अन्य बुकिंग सेवाओं को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव है,नागरिक उपलब्धता,आवेदन और बुकिंग की स्थिति डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे,ऐसी व्यवस्था लागू होने पर बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सकती है, इसके साथ शुल्क, उपलब्ध तारीखों, प्राथमिकता और रद्दीकरण के नियम भी पोर्टल पर स्पष्ट करने होंगे।

कार्यालय के चक्कर कम करने का दावा, लेकिन व्यवस्था कैसे चलेगी?-

डिजिटल बैकुंठपुर की परिकल्पना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराना है, सामान्य तौर पर प्रमाणपत्र, अनुमति, बुकिंग और शिकायत के लिए लोगों को नगर पालिका कार्यालय जाना पड़ता है, कई बार आवेदन की स्थिति जानने या संबंधित अधिकारी से जानकारी लेने के लिए भी नागरिकों को बार-बार कार्यालय पहुंचना पड़ता है, यदि डिजिटल व्यवस्था लागू होती है, तो आवेदन और शिकायत की प्रक्रिया सरल हो सकती है, नागरिक को यह जानकारी मिल सकती है कि आवेदन प्राप्त हुआ या नहीं, वह किस स्तर पर लंबित है और आगे क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन केवल ऐप तैयार कर देना डिजिटल प्रशासन की सफलता की गारंटी नहीं होगा, पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का वास्तविक समाधान, आवेदन की समयबद्ध जांच, कर्मचारियों की जवाबदेही और नियमित तकनीकी रखरखाव भी जरूरी होगा।

डिजिटल व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ डाटा सुरक्षा भी जरूरी-

प्रशांत गुप्ता के विजन में ऑनलाइन सेवाओं और नागरिकों की जानकारी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की परिकल्पना है, इस तरह की व्यवस्था तैयार करने में डाटा सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू होगा, नागरिकों के प्रमाणपत्र, आवेदन, संपर्क विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, इसलिए पोर्टल की सुरक्षा, अधिकृत कर्मचारियों को ही जानकारी तक पहुंच, नियमित बैकअप और तकनीकी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं आवश्यक होंगी, इसके अलावा शहर के सभी नागरिकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की समान सुविधा नहीं होती, ऐसे में डिजिटल सेवाओं के साथ नगर पालिका कार्यालय में सहायता केंद्र या वैकल्पिक आवेदन व्यवस्था भी रखनी होगी, ताकि तकनीकी जानकारी की कमी के कारण कोई नागरिक सेवा से वंचित न रहे।

सिर्फ ऑनलाइन आवेदन नहीं, समय पर समाधान भी सबसे बड़ी कसौटी-

किसी भी डिजिटल शिकायत पोर्टल की सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि कितने लोगों ने शिकायत दर्ज की, बल्कि यह भी जरूरी होगा कि कितनी शिकायतों का समय पर समाधान हुआ,यदि नागरिक ऑनलाइन शिकायत तो दर्ज कर सके,लेकिन उसका निवारण नहीं हो,तो डिजिटल व्यवस्था केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी,इसलिए प्रशांत गुप्ता के प्रस्ताव का महत्वपूर्ण हिस्सा शिकायत की स्थिति और निपटारे की निगरानी है,यदि इसे लागू किया जाता है तो हर शिकायत के लिए जिम्मेदार विभाग,अधिकारी और समय-सीमा निर्धारित करनी होगी, समाधान के बाद नागरिक से प्रतिक्रिया लेने की व्यवस्था भी उपयोगी हो सकती है, यह मॉडल तभी प्रभावी होगा जब नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी डिजिटल प्रक्रिया के अनुरूप प्रशिक्षित हों और ऑनलाइन दर्ज आवेदनों पर नियमित कार्रवाई करें।

सीए की पेशेवर पृष्ठभूमि और डिजिटल प्रशासन का प्रस्ताव

प्रशांत गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भाजपा की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों में उनका नाम चर्चा में है,उनके पेशेवर परिचय के साथ बजट और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर प्रस्तुत डिजिटल विजन भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन रहा है,नगर पालिका के बजट,निविदा और व्यय संबंधी जानकारी को नागरिकों तक पहुंचाने का प्रस्ताव स्थानीय निकाय की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है,हालांकि वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का वास्तविक आकलन केवल पेशेवर योग्यता से नहीं, बल्कि नगर पालिका के कामकाज और योजनाओं को लागू करने की व्यावहारिक समझ से भी होगा,यदि उन्हें पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाता है,तो चुनावी अभियान के दौरान यह भी स्पष्ट करना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में अनुमानित खर्च कितना होगा,उसे संचालित कौन करेगा और उसका रखरखाव किस तरह किया जाएगा।

डिजिटल बैकुंठपुर का विजन और शहर की वर्तमान जरूरतें

बैकुंठपुर में नागरिक सुविधाओं की चर्चा केवल ऑनलाइन आवेदन तक सीमित नहीं है,पेयजल,सफाई,सड़क,नाली,प्रकाश व्यवस्था,व्यापारिक सुविधाएं और सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव जैसे मुद्दे भी नगर पालिका के महत्वपूर्ण दायित्व हैं,डिजिटल प्लेटफॉर्म इन समस्याओं की शिकायत और निगरानी को बेहतर बना सकता है, लेकिन सड़क का निर्माण,नाली की सफाई,पानी की आपूर्ति और कचरे का निस्तारण जैसे काम अंततः जमीन पर ही करने होंगे, इसलिए डिजिटल व्यवस्था को भौतिक विकास का विकल्प नहीं,बल्कि नगर पालिका के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के साधन के रूप में देखना उचित होगा,यदि दोनों व्यवस्थाएं एक-दूसरे के साथ जुड़ती हैं,तो नागरिकों को इसका बेहतर लाभ मिल सकता है।

अब प्रस्ताव की व्यवहारिकता पर उठेंगे सवाल

प्रशांत गुप्ता ने डिजिटल बैकुंठपुर का विजन सार्वजनिक कर दिया है,अब इस प्रस्ताव के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे,ऐप और पोर्टल तैयार करने का खर्च कौन वहन करेगा? तकनीकी संचालन और रखरखाव किसके जिम्मे होगा? क्या सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकेगा? शिकायतों के निपटारे की समय-सीमा कैसे तय होगी? क्या नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी? और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प होगा? इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलने से डिजिटल विजन की व्यवहारिकता समझी जा सकेगी।

टिकट से पहले विकास विजन सार्वजनिक,अब जनता के सामने होगी परीक्षा

बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा से संभावित दावेदार सीए प्रशांत गुप्ता ने तकनीक आधारित नगर प्रशासन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उनका मॉडल नगर पालिका की सेवाओं को मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचाने,नागरिकों की शिकायतों की निगरानी और बजट तथा निविदाओं की जानकारी को पारदर्शी बनाने पर केंद्रित है,यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है,जब कांग्रेस की ओर से आशीष यादव उर्फ लाला ने 13 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है, दोनों के विजन की प्राथमिकताएं अलग हैं, जहां आशीष यादव के संकल्प पत्र में शहरी सुविधाओं, व्यावसायिक विकास,खेल और पेयजल को प्रमुखता दी गई है,वहीं प्रशांत गुप्ता ने डिजिटल प्रशासन को अपने प्रस्ताव का आधार बनाया है, अब सवाल यह है कि डिजिटल बैकुंठपुर की परिकल्पना को तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर किस तरह लागू किया जा सकता है,यदि इसे केवल चुनावी घोषणा से आगे बढ़ाकर स्पष्ट बजट,समय-सीमा,जिम्मेदारी और नागरिकों के लिए आसान व्यवस्था के साथ प्रस्तुत किया जाता है,तभी इसकी वास्तविक उपयोगिता सामने आएगी,फिलहाल यह प्रशांत गुप्ता का प्रस्तावित विजन है,लागू नगर पालिका व्यवस्था नहीं,पार्टी की ओर से अधिकृत टिकट और चुनावी घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसे किस रूप में जनता के सामने रखा जाएगा।

धान खरीदी में किसानों को नहीं पड़ेगा अतिरिक्त आर्थिक बोझ,चट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं

जिला पंचायत की सामान्य सभा में अध्यक्ष मोहित पैकरा ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश...

-संवाददाता-
बैकुंठपुर (कोरिया),26 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जिला पंचायत कोरिया की नवंबर माह की सामान्य सभा में इस बार धान खरीदी का मुद्दा प्रमुखता से उठा, बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित राम पैकरा ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले के किसी भी किसान को धान बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए,किसानों की शिकायतों का निराकरण करना और उन्हें सुगम एवं सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्यक्ष पैकरा ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी परिस्थिति में चट्टा लगाने के लिए मजबूर न किया जाए, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े तथा खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो, उन्होंने हम्माली के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसानों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए, हम्माली का कार्य हम्मालों से ही कराया जाए तथा किसानों से हम्माली के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि न ली जाए,शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को धान खरीदी योजना का पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए, बैठक में अध्यक्ष





के इन निर्देशों से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा, उनकी आर्थिक सुरक्षा और उनकी उपज का सुचारू रूप से उपार्जन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, सामान्य सभा में धान खरीदी के अलावा जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई, अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।



मंत्री के दरबार में सख्ती का फरमान,शिवप्रसादनगर पहुंचते ही बेअसर!

चपरासी के हाथ खरीदी की कमान,ऑनलाइन व्यवस्था में फिर पुराने नाम?

दरबार मंत्री के यहां लगा,खरीदी की कमान पुराने चेहरों को मिली! सहकारिता में निर्देशों का ऐसा हुआ पालन?

मंत्री के निर्देश हवा में,सहकारिता के दरबार में तय हुई खरीदी की नई पटकथा! जेल जा चुके मन्नूलाल को करोड़ों के लेनदेन की जिम्मेदारी, साधना फिर ऑनलाइन खरीदी में सक्रिय?

अनिल बनज की मेहरबानी या नियमों की अनदेखी? विवादों में घिरे कर्मचारियों को फिर मिली धान खरीदी में भूमिका!

मंत्री ने कहा विवादित कर्मचारियों को खरीदी से दूर रखो,अधिकारियों ने चपरासी को ही सौंप दी करोड़ों की कमान!

लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश बेअसर,अनिल बनज के संरक्षण में पुरानों की वापसी? शिवप्रसादनगर खरीदी केंद्र में नई पटकथा!

चपरासी के हाथ करोड़ों का लेनदेन, ऑनलाइन खरीदी में साधना का नाम! मंत्री के निर्देशों की सहकारिता में उड़ी धज्जियां?

पशुपालन ऋण प्रकरण में जेल,अब धान खरीदी में अहम जिम्मेदारी! शिवप्रसादनगर में जवाबदेही पर बड़े सवाल

सहकारिता विभाग में निर्देशों का पालन अपनी सुविधा से? प्रभारी उप पंजीयक अनिल कुमार बनज की भूमिका पर उठे सवाल,पर्दे के पीछे पुराने कर्मचारियों के सक्रिय रहने की शिकायत

करोड़ों के पशुपालन ऋण प्रकरण में मन्नूलाल और साधना कुशवाहा को भी जाना पड़ा था जेल!-

शिवप्रसादनगर समिति से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित पशुपालन ऋण घोटाले में मन्नूलाल और साधना कुशवाहा दोनों के नाम सामने आए, इस प्रकरण में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद दोनों को जेल जाना पड़ा था, ऐसे में सवाल यह है कि जिस कर्मचारी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण में कार्रवाई हो चुकी हो, उसे दोबारा धान खरीदी जैसी संवेदनशील व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का आधार क्या है? मन्नूलाल को करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन के लिए अधिकृत किए जाने और ऑनलाइन खरीदी-टोकन प्रक्रिया में साधना कुशवाहा की भूमिका बने रहने के आरोपों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, क्या विभाग ने पुराने प्रकरणों, जमानत की स्थिति और विभागीय कार्रवाई की समीक्षा किए बिना ही इन्हें फिर से जिम्मेदारी सौंप दी?







मौजूद थे,बैठक का घोषित उद्देश्य किसानों को परेशानी से बचाना और खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था, मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पिछले वर्ष धान खरीदी में अनियमितताओं के आरोपों से घिरे कर्मचारियों को इस वर्ष खरीदी कार्य से दूर रखा जाए,ऐसे कर्मचारियों को दूसरी समितियों में भी संलग्न नहीं किया जाए, यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायतें केवल किसानों की परेशानी तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि सरकारी धन,किसानों के भुगतान और सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ी होती हैं,लेकिन शिवप्रसादनगर की वर्तमान व्यवस्था को लेकर सामने आ रहे आरोपों ने मंत्री के निर्देशों के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं,क्या बैठक के बाद प्रभारी उप पंजीयक ने सभी समितियों से कर्मचारियों की सूची मंगाई? क्या जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें,विभागीय कार्रवाई या आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी थी,उनकी भूमिका का परीक्षण किया गया? क्या विवादित कर्मचारियों को खरीदी से अलग रखने के लिए लिखित आदेश जारी हुए? यदि निर्देश जारी हुए तो शिवप्रसादनगर में उनका पालन किस तरह हुआ? और यदि पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी कौन है?

चपरासी को खरीदी की कमान! करोड़ों के लेनदेन की जिम्मेदारी किस नियम से?- शिवप्रसादनगर समिति में मन्नू लाल को धान खरीदी प्रभारी बनाए जाने की जानकारी सामने आई है, आरोप यह भी है कि करोड़ों के पशुपालन ऋण प्रकरण में वित्तीय अनियमितता में मन्नूलाल व साधन कुशवाहा दोनों को जेल जाना पड़ा था, उन्हें धान खरीदी से जुड़े करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन के लिए अधिकृत किया गया है,यदि यह तथ्य सही है तो यह सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं,बल्कि गंभीर परीक्षण का विषय है,धान खरीदी में केवल बोरियों की गिनती और किसानों से धान लेने का काम नहीं होता,इसमें किसानों के पंजीयन,टोकन,तौल,बारदाना,स्टॉक, ऑनलाइन प्रविष्टि,खरीदी के अभिलेख,भुगतान और वित्तीय लेनदेन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी निर्धारित नियमों, पद और लिखित अधिकारों के अनुसार तय होनी चाहिए,ऐसे में बैंक प्रबंधन को बताना चाहिए कि मन्नू लाल को किस पद और किस आदेश के आधार पर खरीदी प्रभारी बनाया गया? क्या उन्हें वित्तीय लेनदेन का अधिकार भी दिया गया है? यदि हां,तो उसकी सीमा क्या है? क्या इस नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई? क्या समिति के बोर्ड या प्राधिकृत अधिकारी का प्रस्ताव है? क्या बैंक के सेवा नियमों और वित्तीय अधिकारों की सीमा का परीक्षण किया गया? मन्नू लाल के संबंध में यह आरोप भी सामने आया है कि शिवप्रसादनगर समिति से जुड़े पशु ऋण प्रकरण में उनका नाम आया था और इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था, बताया जा रहा है कि वे वर्तमान में अग्रिम जमानत पर हैं। इस मामले की वास्तविक स्थिति एफआईआर,न्यायालयीन आदेश और संबंधित दस्तावेजों से स्पष्ट की जानी चाहिए,केवल आरोप या गिरफ्तारी को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता,लेकिन यदि कोई गंभीर वित्तीय प्रकरण लंबित है तो उसे देखते हुए संवेदनशील वित्तीय जिम्मेदारी सौंपने के औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है, आखिर सहकारी बैंक में जिम्मेदारी का पैमाना क्या है–पद,अनुभव और नियम या फिर किसी अधिकारी की स्वीकृति भर?

प्रभारी मन्नू लाल,ऑनलाइन व्यवस्था में साधना कुशवाहा का नाम?- इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और गंभीर पहलू साधना कुशवाहा से जुड़ा है,आरोप है कि कागजों पर भले ही धान खरीदी का प्रभार मन्नू लाल को दिया गया हो,लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया और टोकन व्यवस्था में साधना कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है,यदि यह जानकारी सही है तो समिति की वास्तविक कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े होते हैं,क्या साधना कुशवाहा को ऑनलाइन टोकन जारी करने या खरीदी की प्रविष्टियां करने का अधिकार दिया गया है? क्या उनका यूजर आईडी सक्रिय है? क्या वे केवल तकनीकी कार्य कर रही हैं या खरीदी के संचालन में भी भूमिका निभा रही हैं? यदि उन्हें खरीदी कार्य से दूर रखने की व्यवस्था थी तो ऑनलाइन प्रक्रिया में उनका नाम कैसे और किस आदेश से आया? साधना कुशवाहा के विरुद्ध पूर्व में धान खरीदी और पशु ऋण से जुड़े मामलों में गंभीर आरोप और शिकायतें सामने आई थीं,उनके संबंध में विभागीय कार्रवाई की जानकारी भी सार्वजनिक हुई थी,ऐसे में मंत्री के निर्देशों के बाद भी यदि उनका नाम खरीदी की ऑनलाइन व्यवस्था में सक्रिय है तो बैंक और सहकारिता विभाग को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए, यहां सवाल किसी व्यक्ति को बिना जांच दोषी ठहराने का नहीं है,सवाल यह है कि जब किसी कर्मचारी की भूमिका को लेकर पहले से शिकायतें और विवाद मौजूद हों,तब उसे खरीदी जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में किस आधार पर शामिल किया गया? क्या विभाग ने पुराने मामलों की स्थिति देखी? क्या सक्षम अधिकारी ने लिखित अनुमति दी? और क्या मंत्री के निर्देशों की अनदेखी हुई?

पर्दे के पीछे पुराने चेहरे,सामने नया प्रभारी?- विभागीय स्तर पर यह आरोप भी सामने आ रहा है कि खरीदी की जिम्मेदारी भले ही नए नाम से दिखाई जा रही हो,लेकिन वास्तविक कामकाज में पुराने कर्मचारी ही सक्रिय हैं,यदि ऐसा है तो फिर नाम बदलने का औचित्य क्या है? क्या यह केवल कागजों पर जिम्मेदारी बदलने की व्यवस्था है,जबकि खरीदी का वास्तविक संचालन पहले की तरह ही चल रहा है? इसका जवाब किसी मौखिक बयान से नहीं, बल्कि दस्तावेजों से मिल सकता है,खरीदी केंद्र की ड्यूटी सूची,प्रभारी नियुक्ति आदेश, ऑनलाइन लॉगिन रिकॉर्ड, टोकन जारी करने वाले यूजर आईडी,दैनिक खरीदी प्रतिवेदन,स्टॉक रजिस्टर और भुगतान से जुड़े अधिकृत हस्ताक्षरों का परीक्षण किया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है,यदि मन्नू लाल प्रभारी हैं तो उनके अधिकारों और कार्यक्षेत्र का लिखित विवरण सार्वजनिक होना चाहिए,यदि साधना कुशवाहा ऑनलाइन प्रक्रिया संचालित कर रही हैं तो उनके अधिकृत किए जाने का आदेश सामने आना चाहिए,और यदि अन्य कर्मचारी वास्तविक रूप से खरीदी का संचालन कर रहे हैं तो उनकी भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि किसी गड़बड़ी की स्थिति में केवल कागजों पर दर्ज प्रभारी को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं होगा,जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी तय होनी चाहिए जिसके हाथ में वास्तविक नियंत्रण और निर्णय की शक्ति थी।

अनिल कुमार बनज के संरक्षण में किसकी व्यवस्था चल रही है?- सहकारिता विभाग के प्रभारी उप पंजीयक अनिल कुमार बनज की भूमिका भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है,सोनपुर समिति से जुड़े पुराने विवादों से लेकर शिवप्रसादनगर की वर्तमान व्यवस्था तक,विभागीय निर्णयों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं,आरोप यह है कि कुछ कर्मचारियों को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार नरमी बरती जाती है, जबकि अन्य मामलों में कार्रवाई की गति अलग दिखाई देती है,हालांकि किसी अधिकारी पर संरक्षण देने का आरोप अपने आप में प्रमाण नहीं है,लेकिन यदि समितियों में विवादित कर्मचारियों की भूमिका बार-बार सामने आ रही है तो विभाग को यह बताना होगा कि शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई और जिम्मेदारियां तय करते समय किन मानकों का पालन किया गया, अनिल कुमार बनज को स्पष्ट करना चाहिए कि शिवप्रसादनगर समिति में मन्नू लाल को खरीदी प्रभारी बनाने की जानकारी उन्हें थी या नहीं? क्या उन्होंने इस नियुक्ति का परीक्षण किया? क्या साधना कुशवाहा की ऑनलाइन भूमिका की जानकारी विभाग को है? क्या मंत्री के निर्देशों के बाद सभी समितियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे? यदि जारी किए गए थे तो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या निरीक्षण हुआ? यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो आदेश सार्वजनिक किए जाएं, और यदि नियमों से हटकर किसी को जिम्मेदारी दी गई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

दरबार में निर्देश,केंद्र में अलग व्यवस्था—मंत्री तक पहुंचेगी असली रिपोर्ट?- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की बैठक में किसानों की सुविधा, पारदर्शी खरीदी और विवादित कर्मचारियों को खरीदी से दूर रखने की बात हुई थी,लेकिन अब शिवप्रसादनगर से सामने आ रही जानकारी के बाद यह सवाल उठता है कि क्या मंत्री तक खरीदी केंद्रों की वास्तविक स्थिति पहुंचाई जा रही है या उन्हें केवल तैयारियों की औपचारिक रिपोर्ट दी जा रही है? किसी बैठक में निर्देश देना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है,लेकिन उन निर्देशों का पालन कराना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, यदि मंत्री के निर्देशों के बावजूद समिति में उन्हीं कर्मचारियों की भूमिका बनी रहती है जिनके संबंध में पहले से शिकायतें हैं, तो यह जानना जरूरी है कि चूक कहां हुई–समिति स्तर पर, बैंक प्रबंधन में या सहकारिता विभाग के स्तर पर? मंत्री को भी यह जानकारी दी जानी चाहिए कि उनके निर्देशों के बाद कितने कर्मचारियों को खरीदी से अलग किया गया,कितने केंद्रों में जिम्मेदारियां बदली गईं और किन समितियों में पुराने विवादित कर्मचारियों की भूमिका अब भी बनी हुई है।

किसानों के नाम पर खरीदी, लेकिन जवाबदेही किसके नाम?- धान खरीदी का पूरा तंत्र किसानों के भरोसे पर चलता है, किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पहुंचता है तो उसे उम्मीद रहती है कि उसका टोकन समय पर कटेगा, तौल सही होगी,भुगतान में देरी नहीं होगी और उसकी उपज का रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से दर्ज होगा। लेकिन यदि खरीदी केंद्र में ही यह स्पष्ट नहीं है कि प्रभारी कौन है,ऑनलाइन प्रक्रिया कौन चला रहा है और वित्तीय अधिकार किसके पास हैं, तो व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजिमी है,इसलिए शिवप्रसादनगर का मामला केवल मन्नू लाल या साधना कुशवाहा की तैनाती तक सीमित नहीं है, यह सहकारी संस्थाओं में जिम्मेदारी निर्धारण, वित्तीय अधिकारों और विभागीय निगरानी की परीक्षा है, किसी भी कर्मचारी को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी कर्मचारी को बिना स्पष्ट आदेश और अधिकारों की जांच के संवेदनशील जिम्मेदारी भी नहीं दी जानी चाहिए।

बैंक और सहकारिता विभाग से सीधे सवाल

1. शिवप्रसादनगर समिति में मन्नू लाल को खरीदी प्रभारी बनाने का लिखित आदेश किस अधिकारी ने जारी किया?
2. क्या मन्नू लाल को करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन का अधिकार दिया गया है? यदि हां, तो किस नियम और आदेश के तहत?
3. उनके विरुद्ध पशु ऋण प्रकरण में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है?
4. साधना कुशवाहा का नाम ऑनलाइन टोकन और खरीदी प्रक्रिया में किस आधार पर सक्रिय है?
5. क्या साधना कुशवाहा को खरीदी कार्य से दूर रखने के संबंध में कोई लिखित आदेश जारी हुआ था?
6. ऑनलाइन टोकन,खरीदी प्रविष्टि और स्टॉक संधारण का वास्तविक काम कौन कर रहा है?
7. क्या मंत्री के निर्देशों के बाद विवादित कर्मचारियों की सूची तैयार कर सभी समितियों को भेजी गई थी?
8. प्रभारी उप पंजीयक अनिल कुमार बनज ने शिवप्रसादनगर समिति की तैनाती और वित्तीय अधिकारों का परीक्षण किया है या नहीं?
9. यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर शिकायत या आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसे संवेदनशील जिम्मेदारी देने का आधार क्या है?
10. क्या बैंक प्रबंधन ऑनलाइन लॉगिन रिकॉर्ड, ड्यूटी सूची और खरीदी प्रभारी के आदेश की जांच कर सार्वजनिक करेगा?

अब निर्देशों की नहीं,कार्रवाई की परीक्षा है- मंत्री के निवास पर बैठक हुई, निर्देश दिए गए और किसानों को राहत देने का भरोसा जताया गया,लेकिन शिवप्रसादनगर समिति से उठ रहे सवालों का जवाब केवल प्रेस विज्ञप्ति या मौखिक सफाई से नहीं मिलेगा,इसके लिए नियुक्ति आदेश,वित्तीय अधिकार,ऑनलाइन लॉगिन और वास्तविक कार्यप्रणाली की जांच जरूरी है,यदि मन्नू लाल की नियुक्ति नियमसम्मत है तो उसका आदेश सामने रखा जाए, यदि साधना कुशवाहा ऑनलाइन व्यवस्था में अधिकृत हैं तो उसका आधार बताया जाए, यदि पुराने कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं है तो लॉगिन और ड्यूटी रिकॉर्ड से स्थिति स्पष्ट की जाए,और यदि मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो,क्योंकि धान खरीदी का दरबार केवल बैठक में सजाने से व्यवस्था पारदर्शी नहीं होती,निर्देशों की असली परीक्षा खरीदी केंद्र में होती है,वहां यदि कागजों पर एक चेहरा, ऑनलाइन व्यवस्था में दूसरा और वास्तविक संचालन में तीसरा चेहरा दिखाई दे,तो सवाल उठना तय है–शिवप्रसादनगर में धान खरीदी की कमान आखिर किसके हाथ में है और जवाबदेही किसकी होगी?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

धान खरीदी शुरू होने से पहले मंत्री के निवास पर सहकारिता विभाग का दरबार सजा, किसानों को परेशान नहीं करने, खरीदी में पारदर्शिता रखने और पिछले वर्ष की अनियमितताओं में आरोपित कर्मचारियों को इस बार खरीदी कार्य से दूर रखने के निर्देश दिए गए,बैठक में मौजूद अधिकारियों और समिति प्रबंधकों ने निर्देश सुने, व्यवस्था सुधारने का भरोसा भी दिया गया होगा,लेकिन अब सवाल यह है कि उस दरबार में दिए गए निर्देशों का खरीदी केंद्रों तक पहुंचते-पहुंचते क्या हुआ? क्या निर्देशों का पालन हुआ या फिर फाइलों में निर्देश और समितियों में व्यवस्था अपने-अपने रास्ते चल पड़ी? शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र से सामने आ रही जानकारी ने इसी सवाल को फिर खड़ा कर दिया है,आरोप है कि यहां धान खरीदी की जिम्मेदारी मन्नू लाल नामक कर्मचारी को सौंप दी गई है,जो समिति में चपरासी के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं,इतना ही नहीं,उनके पास खरीदी से जुड़े बड़े वित्तीय लेनदेन की जिम्मेदारी भी दिए जाने की बात सामने आ रही है,दूसरी ओर,ऑनलाइन टोकन और खरीदी प्रक्रिया में साधना कुशवाहा का नाम सक्रिय होने का आरोप है,जबकि उनके संबंध में पूर्व में सामने आई शिकायतों और कार्रवाई के बाद उन्हें खरीदी कार्य से दूर रखने की अपेक्षा की जा रही थी,यानी कागजों पर प्रभारी कोई और, ऑनलाइन प्रक्रिया में नाम किसी और का और पर्दे के पीछे कामकाज संभालने वाले चेहरे भी कथित तौर पर पुराने! ऐसे में सवाल उठता है कि शिवप्रसादनगर समिति में धान खरीदी आखिर किसके नियंत्रण में चल रही है? जवाबदेही किसकी होगी? और सबसे अहम–मंत्री के निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की थी, वे आखिर कर क्या रहे हैं?

मंत्री ने कहा था विवादितों को दूर रखो,समिति में जिम्मेदारी किस आधार पर बंटी?- 11 नवंबर को वीरपुर स्थित अपने निवास पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर बैठक की थी,बैठक में प्रभारी उप पंजीयक सहकारिता अनिल कुमार बनज,जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी दिलीप दुबे और समिति प्रबंधक

CMYK

साउथ में काम करने पर बॉलीवुड ड्रॉपआउट कहलाईं जेनेलिया डिसूजा

शादी पर करियर खत्म होने के ताने मिले, 'वेड' से दिया आलोचकों को जवाब

कभी पहली फिल्म के प्रदर्शन पर सवाल उठे, तो कभी साउथ में काम करने पर उन्हें 'बॉलीवुड ड्रॉपआउट' कहा गया। जिस अभिनेत्री को एक डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेने को लेकर आश्वस्त नहीं था,उन्होंने 'जाने तू... या जाने ना' से पहचान बनाई। शादी पर उनके करियर खत्म होने के ताने मिले। करीब दस साल फिल्मों से दूर रहने के बाद उनकी वापसी पर भी निराशा जताई गई। लेकिन मराठी फिल्म 'वेड' की सफलता से उन्होंने खुद को साबित किया। यह कहानी है जेनेलिया डिसूजा देशमुख की, जिन्होंने तानों, असफलताओं और लंबे ब्रेक के बावजूद पहचान बनाई।

परिवार की झिझक के बीच शुरू हुआ फिल्मी सफर

जेनेलिया डिसूजा का जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार फिल्मी दुनिया से नहीं जुड़ा था। इसलिए अभिनय को करियर बनाने का फैसला आसान नहीं था। शुरुआत में परिवार उन्हें फिल्मों में भेजने को लेकर झिझक रहा था। हालांकि,उनकी मां ने साथ दिया। फिल्मों में आने से पहले जेनेलिया मॉडलिंग कर चुकी थीं। अमिताभ बच्चन के साथ पार्कर पेन के विज्ञापन से उन्हें पहचान मिली। इसी दौरान उन्हें 'तुझे मेरी कसम' का ऑफर मिला। शुरुआत में वह अभिनय को लेकर आश्वस्त नहीं थीं। फिल्म की टीम करीब दो महीने तक उनसे संपर्क करती रही। इसके बाद उन्होंने काम करने का फैसला किया।

पहली फिल्म के बाद मिली चुनौती,डायरेक्टर को था संदेह

साल 2003 में रिलीज हुई 'तुझे मेरी कसम' से जेनेलिया ने रितेश देशमुख के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया। दोनों की मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। हालांकि, पहली फिल्म से उन्हें हिंदी सिनेमा में बड़ी पहचान नहीं मिली। 2010 में टेलीग्राफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में जेनेलिया ने बताया था कि 'जाने तू... या जाने ना' के डायरेक्टर अब्बास टायरवाला उन्हें कास्ट करने को लेकर आश्वस्त नहीं थे। इसकी वजह उनकी पहली फिल्म का प्रदर्शन था। उन्हें ऐसे नए चेहरे को लेने पर संदेह था,जिसका बॉलीवुड डेब्यू असफल माना जा रहा था। जेनेलिया ने इस चुनौती को पीछे छोड़ दिया। आगे चलकर यही फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बनी।

साउथ की फिल्मों में काम करने पर मिला 'बॉलीवुड ड्रॉपआउट' का ताना

पहली हिंदी फिल्म के बाद जेनेलिया ने तमिल फिल्म 'बॉयज' और तेलुगु फिल्म 'सत्यम' में काम किया। उन्होंने 2003 में ही तीन अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने साउथ में लगातार काम किया और तमिल-तेलुगु फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने सिद्धार्थ के साथ 'बॉयज','ऑरेंज','बोम्मरिल्लु' और 'रेडी' जैसी फिल्मों में काम किया। 'बोम्मरिल्लु' में उनके अभिनय को खास सराहना मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का तेलुगु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। साउथ में काम करने के दौरान उन्हें एक सोच का सामना करना पड़ा। जुलाई 2023 में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में जेनेलिया ने बताया था कि उस दौर में कहा जाता था कि बॉलीवुड में असफल कलाकार साउथ की फिल्मों में चले जाते हैं। ऐसे कलाकारों को 'बॉलीवुड ड्रॉपआउट' कहा जाता था। उन्होंने इस धारणा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके मुताबिक, साउथ में काम करते हुए ही उन्हें अभिनय से प्यार हुआ और वहां के दर्शकों ने उन्हें खूब अपनाया।

'मस्ती' और 'जाने तू... या जाने ना' से हिंदी में बनाई पहचान

साउथ में काम के साथ जेनेलिया हिंदी फिल्मों में भी सक्रिय रहीं। 2004 में वह कॉमेडी फिल्म 'मस्ती' में नजर आईं। इसमें विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख भी थे। फिल्म सफल रही और जेनेलिया को हिंदी दर्शकों के बीच पहचान मिली। 2008 उनके करियर का खास साल रहा। पहले वह अक्षय खन्ना और परेश रावल के साथ 'मेरे बाप पहले आप' में नजर आईं। इसके बाद तेलुगु फिल्म 'रेडी' में राम के साथ काम किया। इसके बाद आमिर खान प्रोडक्शंस की 'जाने तू...या जाने ना' रिलीज हुई। इसमें उन्होंने अदिति का किरदार निभाया। इमरान खान के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद आई। फिल्म की सफलता ने उन्हें हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने 'लाइफ पार्टनर', 'चांस पे डांस', 'फोर्स' और 'तेरे नाल लव हो गया' जैसी फिल्मों में काम किया। साउथ में भी 'उरुमी' जैसी फिल्मों से सफर जारी रखा। उनके करियर में कुछ फिल्में असफल भी रहीं।

शादी पर मिले ताने,लोगों ने कहा- करियर खत्म हो जाएगा

रितेश देशमुख और जेनेलिया की प्रेम कहानी 'तुझे मेरी कसम' के सेट पर शुरू हुई थी। करीब एक दशक तक डेटिंग के बाद दोनों ने 3 फरवरी 2012 को शादी कर ली। शादी के बाद जेनेलिया ने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया। इस पर उन्हें लोगों की बातें भी सुननी पड़ीं। 2020 में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के समय लोगों ने उनसे कहा था कि शादी के बाद लड़की का करियर खत्म हो जाता है। उन्होंने साफ किया कि ऐसी बातें उन्हें रितेश से शादी के फैसले से पीछे नहीं हटा सकती थीं। उन्होंने बताया था कि हिंदी फिल्मों में कम नजर आने के बावजूद वह साउथ में साल के 365 दिन काम करती थीं। करीब दस साल लगातार काम करने के बाद वह परिवार को समय देना चाहती थीं। शादी के बाद उनके दो बेटे रियान और राहिल हुए। जेनेलिया ने अभिनय से दूरी बनाने को अपना फैसला बताया था। लोगों ने यह भी मान लिया था कि रितेश या उनके परिवार ने उन्हें काम करने से रोका है। उन्होंने इस धारणा को गलत बताया।

अभिनय से ब्रेक के दौरान पति के साथ प्रोडक्शन शुरू किया

फिल्मों से दूरी के दौरान जेनेलिया दूसरे कामों में व्यस्त रहीं। रितेश के साथ उन्होंने 'मुंबई फिल्म कंपनी' के जरिए फिल्म निर्माण में कदम रखा। दोनों मराठी फिल्मों के निर्माण से जुड़े। इस दौरान जेनेलिया ने निर्माता के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। 'लय भारी' और 'मौली' जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी प्रोडक्शन कंपनी की भागीदारी रही। बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी वापसी के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। 30 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई 'वेड' में जेनेलिया ने श्रावणी का किरदार निभाया। यह ऐसी महिला की कहानी थी, जो अपने पति के साथ रिश्ते और जिंदगी की मुश्किलों से जूझती है। फिल्म में जेनेलिया के अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया। इंडियन एक्सप्रेस की 15 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म तब तक करीब 44.92 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी थी। यह 'सैराट' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई थी।

'सितारे जमीन पर' के बाद भी जारी रहा सफर

करीब 10 साल के ब्रेक के बाद मराठी फिल्म 'वेड' से वापसी करने वाली जेनेलिया ने काम जारी रखा। 2023 में वह 'ट्रायल पीरियड' में नजर आईं। 2025 में आमिर खान के साथ 'सितारे जमीन पर' में दिखाई दीं। इसमें उन्होंने आमिर की पत्नी सुनीता का किरदार निभाया। इसी साल उन्होंने साउथ सिनेमा में भी वापसी की। वह तेलुगु और कन्नड़ फिल्म 'जूनियर' में विजया सौजन्या के किरदार में नजर आईं। 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 'मस्ती 4' में भी उनकी स्पेशल अपीयरेंस रही। साल 2026 में जेनेलिया पति रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आईं। उन्होंने फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई भोसले का किरदार निभाया। वह इस फिल्म से अभिनेत्री के साथ निर्माता के तौर पर भी जुड़ी रहीं। उनकी अगली फिल्म 'गनमास्टर जी9' है, जिसमें इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं। यह 27 नवंबर 2026 को रिलीज होगी।



सरकार बोली....फ्लिक्स भारत में पाकिस्तानी कंटेंट न दिखाए...

2025 की एडवाइजरी का पालन हो,पहलगाम हमले के बाद बैन किया था पाकिस्तानी कंटेंट

केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स से कहा है कि वह पाकिस्तान में बने किसी भी कंटेंट को भारत में स्ट्रीम न करे। न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी वेबसीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' के भारत में रिलीज होने की आशंका को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद मंत्रालय ने कंपनी से 8 मई 2025 की एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में बने कंटेंट को भारत में नहीं दिखाया जा सकता।



दो फिल्म संगठनों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा

सीरीज की संभावित रिलीज के विरोध में भारत के दो फिल्म संगठनों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इनमें ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान को आतंकवाद से जुड़ा देश बताते हुए सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने लिखा कि हम पाकिस्तानी शो का विरोध करता है। हमारे देश में पाकिस्तानी कलाकारों का स्वागत नहीं हो सकता। अगर यह सीरीज भारत में रिलीज हुई तो वह नेटफ्लिक्स के सभी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग रुकवा देगा।

तीन पीढ़ियों और छह प्रेम कहानियों पर बनी सीरीज : सीरीज की कहानी तीन पीढ़ियों और छह प्रेम कहानियों पर आधारित है। इसमें प्यार,परिवार,रिश्तों और पुराने जख्मों को दिखाया गया है। इसका पहला पार्ट 4 दिसंबर को दुनियाभर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। हालांकि,भारत में यह सीरीज रिलीज होगी या नहीं,अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नेटफ्लिक्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। सीरीज का निर्देशन और निर्माण मोमिना दुरैद ने किया है। इसकी कहानी फरहत इश्तियाक के इसी नाम के उर्दू उपन्यास पर आधारित है। इसमें फवाद खान,माहिरा खान,हानिया आमिर, सनम सईद,अहद रजा मीर,इकरा अजीज,हमजा अली अब्बासी और माया अली नजर आएंगे।

पाकिस्तान के मंत्री बोले...कला और संस्कृति को हथियार बनाया जा रहा : विवाद पर पाकिस्तान के मंत्री अहसान इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत पहले खेल,फिर पानी और अब कला-संस्कृति को हथियार बना रहा है। बेंगलुरु में एक अन्य पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज दर-ए-निजात की दो स्क्रीनिंग सोशल मीडिया पर विरोध के बाद रद्द कर दी गईं। ये कार्यक्रम 28 नवंबर और 5 दिसंबर को होने थे। पुलिस के मुताबिक,आयोजकों ने खुद दोनों कार्यक्रम रद्द किए। उन्होंने इसके लिए पुलिस से अनुमति भी नहीं ली थी। पहली स्क्रीनिंग फ्रेजर टाउन के एक रेस्टोरेंट में होनी थी। दूसरी स्क्रीनिंग माउवी प्राइवेट थिएटर में प्रस्तावित थी,जहां मेहमानों के लिए पाकिस्तानी कपड़े पहनने का ड्रेस कोड था। सीरीज का निर्देशन साकिब खान ने किया है।

'पंचायत' सीजन-5 प्राइम पर 3 दिसंबर को रिलीज होगी

सचिव और बनराकस के बीच खींचतान दिखेगी, 5 ओटीटी सीजन वाली दूसरी इंडियन सीरीज बनेगी

प्राइम वीडियो ने 'पंचायत' के सीजन 5 की रिलीज डेट का ऐलान किया। यह सीजन 3 दिसंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। रिलीज के बाद 'पंचायत' पांच सीजन पूरे करने वाली भारत की दूसरी वेब सीरीज बन जाएगी। टीवीएफ की ही वेब सीरीज 'गुल्लक' ओटीटी पर पांच सीजन पूरे करने वाली भारत की पहली सीरीज है। यह पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा सोनी लिव पर स्ट्रीम होती है। इसका पहला सीजन 2019 में रिलीज हुआ था। पंचायत के नए सीजन में नई कहानी में दर्शक फिर फुलेरा गांव और सचिवजी के साथ लौटेंगे। शो में गांव की राजनीति, बदलते रिश्ते और हल्का-फुल्का हास्य देखने को मिलेगा। शो में सचिव और बनराकस के बीच खींचतान दिखेगी।

ये कलाकार लौटेंगे...

पंचायत सीजन 5 का निर्माण द वायरल फीवर ने किया है। सीरीज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव,नीना गुप्ता,सुनीता राजवर, फैजल मलिक,चंदन रॉय,दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक नजर आएंगे। शो का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। इसके क्रिएटर्स दीपक कुमार मिश्रा,चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार हैं।

2020 में शुरू हुई थी पंचायत की कहानी

पंचायत का पहला सीजन 3 अप्रैल 2020 को प्राइम वीडियो पर आया था। इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषेक त्रिपाठी की कहानी दिखाई गई थी। अच्छी नौकरी नहीं मिलने पर वह उत्तर प्रदेश के काल्पनिक गांव फुलेरा में पंचायत सचिव की नौकरी करने पहुंचता है। शहर में पले-बढ़े अभिषेक के लिए गांव का माहौल नया होता है। वह गांव के लोगों, उनकी समस्याओं और पंचायत की राजनीति के बीच अपनी नौकरी करता है। साथ ही उसका सपना एमबीए करके बेहतर नौकरी पाने का है। पहले सीजन को मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद दूसरा सीजन 2022 में आया। तीसरा सीजन 2024 और चौथा सीजन जून 2025 में रिलीज हुआ।

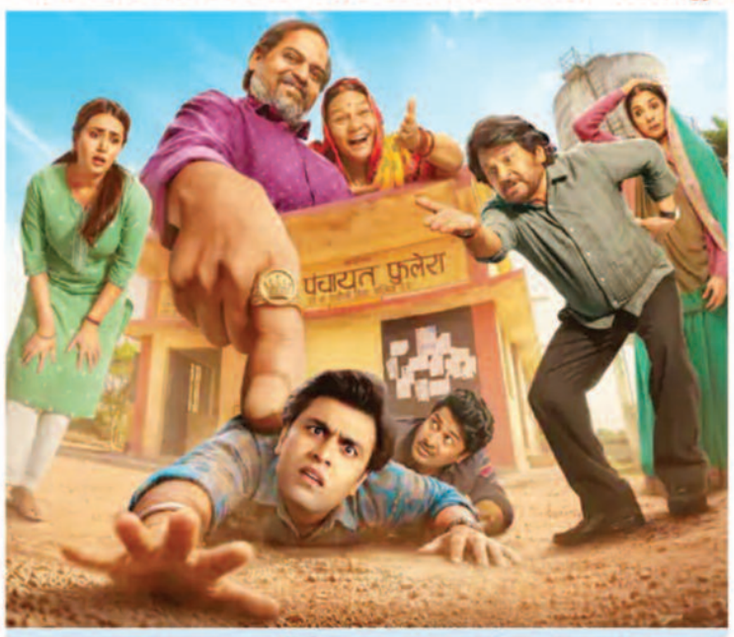

पंचायत 2 को मिला था पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ओटीटी अवॉर्ड

सीरीज को दर्शकों के साथ-साथ पुरस्कार भी मिले हैं। नवंबर 2023 में गोवा में हुए 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पंचायत 2 को बेस्ट वेब सीरीज का पहला ओटीटी अवॉर्ड दिया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, इस पुरस्कार के लिए 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म की 10 भाषाओं की 32 सीरीज को चुना गया था। इनमें से चार सीरीज को फाइनल नॉमिनेशन मिला था।

चौथे सीजन ने बनाया था व्यूअरशिप रिकॉर्ड : प्राइम वीडियो के मुताबिक, पंचायत के चौथे सीजन को रिलीज के पहले हफ्ते में 180 से ज्यादा देशों में देखा गया था। यह 42 से ज्यादा देशों में प्लेटफॉर्म की टॉप-10 ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हुआ था। भारत में यह 95% पिन कोड तक पहुंचा था। प्लेटफॉर्म ने इसे सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग सीजन भी बताया था।

प्राइम वीडियो और द वायरल फीवर का बयान : प्राइम वीडियो इंडिया में स्ट्रीम्ड कंटेंट एक्विजिशन के डायरेक्टर और हेड मनीष मेंघानी ने पंचायत 5 को लेकर कहा, 'कुछ कहानियां समय के साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। पंचायत ऐसी ही एक कहानी है। ' उन्होंने कहा...'भारत की सबसे सफल और पहचानी जाने वाली फ्रेंचाइजी में शामिल इस सीरीज का पांचवें सीजन के साथ लौटना गर्व की बात है। यह उपलब्धि इसकी खास यात्रा और दर्शकों से लगातार जुड़ाव दिखाती है। 'द वायरल फीवर के प्रेसिडेंट विजय कोशी ने कहा कि दर्शकों ने फुलेरा और उसके लोगों को जो प्यार दिया है, उससे उनका भरोसा मजबूत हुआ है। कोशी ने कहा,'सीजन 5 में हम इस पसंदीदा कलाकार समूह की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नई चुनौतियां, बदलते रिश्ते और अचानक आने वाले मोड़ गांव की जिंदगी के नए पहलू दिखाएंगे। 'उन्होंने आगे कहा...'पंचायत ओटीटी पर पांचवें सीजन तक पहुंचने वाले भारत के सिर्फ दो शोज में से एक है।

खेल समाचार

इंडिया-ए ने श्रीलंका-ए को दिया 318 रन का टारगेट

तिलक अभिषेक और शाहबाज की फिफ्टी,वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 40 रन

दोहा,26 नवम्बर 2026। इंडिया-ए ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए को 318 रन का टारगेट दिया है। दोहा में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 317 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 63 गेंदों पर 78 रन की पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और एक छक्का लगाया। कप्तान तिलक वर्मा ने 53 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल रहा। शाहबाज अहमद 54 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 4 छक्के लगाए। पिछले मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 40 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। श्रीलंका से रविंदु फर्नांडो, जनित लियानगे और निपुण धनंजय ने 2-2 विकेट लिए। आखिरी ओवर में भारत-ए ने 9 रन बनाए और एक विकेट गंवाया। गरुका संकेथ की दूसरी गेंद पर हर्षित राणा बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हर्ष दुबे ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया। 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर एक रन लिया। तनुष कोटियन ने चौथी गेंद पर सिंगल लिया। पांचवीं गेंद पर शाहबाज ने भी एक रन बनाया। आखिरी गेंद पर जनिथ लियानगे ने तनुष को रविंदु फर्नांडो के हाथों कैच करा दिया। तनुष 30 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए। 48वें ओवर की



दूसरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। अगली गेंद वाइड रही। इसके बाद शाहबाज और तनुष कोटियन ने लगातार चार गेंदों पर एक-एक रन लिया। गरुका संकेथ के इस ओवर में 12 रन बने। 46वें ओवर की दूसरी गेंद वाइड रही। इसके बाद शाहबाज अहमद ने अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। पांचवीं गेंद पर तनुष कोटियन ने चौका लगाया। गरुका संकेथ के इस ओवर में 12 रन आए। 45वें ओवर में वनुजा सहान ने महज 4 रन दिए। ओवर की पहली गेंद पर तनुष कोटियन ने कोई रन नहीं लिया। इसके बाद अगली तीन गेंदों पर कोटियन और शाहबाज अहमद ने एक-एक रन लिया। पांचवीं गेंद पर शाहबाज ने फिर सिंगल लिया, जबकि आखिरी गेंद पर कोटियन ने कोई रन नहीं बनाया। 43वें ओवर की पहली गेंद पर तनुष कोटियन ने चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर शॉर्ट कवर पर निपुण धनंजय ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। कोटियन ने चौथी गेंद पर सिंगल लिया। आखिरी दो गेंदों पर शाहबाज अहमद ने 3 रन बटोरे। वनुजा सहान के इस ओवर में कुल 8 रन बने। 39वें ओवर की पांचवीं गेंद पर निपुण धनंजय ने सूर्यांश शेडगे को आउट कर दिया। सूर्यांश ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर डीप मिडविकेट की ओर गई। रविंदु फर्नांडो ने आगे की तरफ डाइव लगाकर कैच लपका। थर्ड अंपायर ने रीप्ले देखने के बाद कैच को सही माना। सूर्यांश 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। रविंदु फर्नांडो ने 37वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रिंकू ने लेग साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। रिंकू इस फैसले से नाखुश दिखे और उन्होंने अंपायर के सामने नाराजगी भी जताई। हालांकि,रीप्ले में गेंद पर इनसाइड एज नजर आया। रिंकू ने 21 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस दौरान एक छक्का लगाया। रविंदु फर्नांडो ने 33वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तिलक ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पिछले पैर पर लगी। अंपायर ने तुरंत उन्हें आउट दे दिया। तिलक ने 66 गेंदों पर 53 रन बनाए। इस दौरान 3 चौके और एक छक्का लगाया। 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने रविंदु फर्नांडो की फुल लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से खेलकर बाउंड्री तक पहुंचाया। 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर निपुण धनंजय ने कुमार कुशाग्र को आउट कर दिया। कुशाग्र ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर शॉर्ट मिडविकेट पर गई।

हॉकी इंडिया लीग का नया सत्र जनवरी के पहले सप्ताह से,खिलाड़ियों की नीलामी 7 दिसंबर को

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2026। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2026-27 सत्र की प्रमुख तारीखों और कार्यक्रम की घोषणा कर दी। प्रतियोगिता जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में शुरू होगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 7 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नए सत्र के लिए टीमों के गठन की दिशा में यह अगला बड़ा कदम होगा। आगामी सत्र में पुरुष वर्ग में छह और महिला वर्ग में चार फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। लीग के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतिभाओं को प्रमुख मंच उपलब्ध कराने की परंपरा जारी रहेगी। तैयारियां तेज होने के साथ ही फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों के आपसी आदान-प्रदान और उन्हें टीम में बनाए रखने की प्रक्रिया पूरी करेंगी। इसके बाद उनका ध्यान नीलामी पर होगा।



घोषित कार्यक्रम के अनुसार, फ्रेंचाइजी को अपने प्रस्तावित खिलाड़ी आदान-प्रदान की जानकारी 29 नवंबर 2026 तक सीधे संबंधित फ्रेंचाइजी को देनी होगी। आधिकारिक ट्रेडिंग विंडो 29 नवंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे खुलेगी और 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे बंद होगी। इसके बाद फ्रेंचाइजी को 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक खिलाड़ियों को स्थायी रूप से टीम से रिलीज करने की जानकारी हीरो हॉकी इंडिया लीग को देनी होगी और अपनी अंतिम टीम सूची जमा करनी होगी। उसी दिन शाम 5 बजे हीरो हॉकी इंडिया लीग सभी फ्रेंचाइजी को नीलामी के लिए तैयार संयुक्त खिलाड़ी सूची उपलब्ध कराएगी। इसके बाद फ्रेंचाइजी के पास 3 दिसंबर को शाम 5 बजे तक उन खिलाड़ियों की सूची जमा करने का समय होगा,जिन्हें वे पिछले सत्र में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए पंजीकृत सूची से हटाना चाहती हैं। रांची रॉयल्स की पुरुष टीम और हीरो हॉकी इंडिया लीग गवर्निंग काउंसिल की टीम के खिलाड़ी भी नीलामी की सूची में शामिल होंगे। भारतीय महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने लीग की वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा,'मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि हीरो हॉकी इंडिया लीग एक और सत्र के लिए लौट रही है। यह लीग भारतीय खिलाड़ियों के लिए दुनिया के कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक महत्वपूर्ण मंच रही है। विशेष रूप से महिला प्रतियोगिता हमें अपनी प्रतिभा दिखाने और अधिक युवा लड़कियों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करने का शानदार अवसर देती है। 'भारतीय पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी लीग की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने भारतीय हॉकी के पूरे तंत्र को मजबूत करने में लीग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। हरमनप्रीत ने कहा, 'यह शानदार खबर है कि हीरो हॉकी इंडिया लीग जनवरी में वापस आ रही है। हर सत्र के साथ प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता है और भारतीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ मैदान साझा करने का अवसर मिलता है।

कांग्रेस ने निकाला संविधान रक्षा मार्च...वोट चोरी और एसआईआर पर सरकार को घेरा

मोदी वाशिंग पाउडर संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा

2029 में राहुल गांधी संभालेंगे देश : दीपक बैज







रायपुर,26 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रायपुर में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर संविधान रक्षा मार्च निकालकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। कांग्रेस पार्टी ने गांधी मैदान से अंबेडकर चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पैदल मार्च निकालकर सियासी मैदान में अपनी सक्रियता का संदेश देने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, मोदी वाशिंग पाउडर संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देश में एक तरफ बेचने का काम चल रहा है,दूसरी तरफ बचाने का काम चल रहा है। 2029 में हमारे नेता राहुल गांधी देश की कमान संभालेंगे। इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत,नवनियुक्त सहप्रभारी हरनाम सिंह और जितेंद्र बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, विधायक,पूर्व मंत्री और प्रदेशभर से पहुंचे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पैदल मार्च के जरिए कांग्रेस ने संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं, मताधिकार और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। दरअसल, एसआईआर और कथित वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होना जरूरी है, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न कटे और किसी अपात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में जगह न मिले। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश की है।

देश में वोट चोरी से सत्ता हासिल कर रही मोदी सरकार : बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देशभर में संविधान रक्षा मार्च चल रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना,जिसमें आम नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। संविधान रक्षा का मतलब है,सबके जीने का अधिकार,समता और समानता का अधिकार,स्वतंत्र रूप से सरकार चुनने का अधिकार,बोलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने का अधिकार है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला लोकतांत्रिक देश भारत देश है। संविधान के आधार पर सरकार बनती है,संविधान के आधार पर कानून बनती है,संविधान के आधार पर देश के नियम बनाये जाते हैं,लेकिन वर्तमान सरकार मनमानी कर रही है। अपने अनुकूल मतदाता चुन रही है। संविधान को बचाने का काम हमेशा हम लोगों ने किया। मोदी सरकार पूरे देश में वोट चोरी से सत्ता हासिल कर रही है। 2028 में हमारे नेता देश का कमान संभालेंगे,यह संकल्प हम लेते हैं।

संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही सरकार : सुखदेव

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाह सरकार लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हम आज संविधान बचाओ मार्च निकालकर संकल्प ले रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं हमारी इस लड़ाई में पूरे देशभर के 60 प्रतिशत से अधिक मतदाता हमारा साथ दे रहे हैं। हमारी लड़ाई संविधान और भारत के लोकतंत्र के लिए हमेशा जारी रहेगी।

संविधान रक्षक होने का ढोंग कर रही भाजपा : नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। इस देश को स्वतंत्र करवाया और संविधान बनाकर देश की जनता को देश चलाने का अधिकार दिया। इसी संविधान की रक्षा करने के लिए हम यहां आए हैं। आज संविधान दिवस है। भाजपा जाति, धर्म में बांटकर देश में नफरत फैला रही है, फूट डाल रहे हैं, ये संविधान रक्षक होने का ढोंग कर अपनी सत्ता कायम रखने संविधान की हत्या करने में लगे हैं। आज हम उनसे हिसाब मांगने आए हैं। महंत ने कहा, छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। हमे हमारे ही अधिकारों से जबरिया बेदखल किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे देश की आम जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। संवैधानिक संस्थानों का दुरूपयोग हो रहा है, आज उसकी रक्षा करने की जवाबदारी हम और आप पर है। देश के संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है,जिसके खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना है। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने किया। संविधान रक्षा मार्च कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर,पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया,पूर्व मंत्री मोहन मरकाम,पूर्व मंत्री अमरजीत भगत,पूर्व मंत्री रूद्र कुमार गुरू, पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिला भेड़िया,पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम,सांसद फूलोदेवी नेताम, सांसद ज्योत्सना मंहत,प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला,विधायक लखेश्वर बघेल,सावित्री मंडावी,विक्रम मंडावी,संगीता सिन्हा,द्वारिकाधीश यादव,संदीप साहू, कुंवर सिंह निषाद,हर्षिता बघेल,द्वारिकाधीश यादव,कविता प्राणलहरे,चातुरीनंद,दिलीप लहरिया,शेषराज हरबंश,इंद्रशाह मंडावी, अंबिका मरकाम,ओंकार साहू, बालेश्वर साहू समेत अन्य नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।

डीएमएफ घोटाला...अनिल टुटेजा की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

कहा-अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं,ईडी ने लगाया 20 से 25प्रतिशत कमीशनखोरी का आरोप

बिलासपुर,26 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने 25 नवंबर को यह फैसला सुनाया। इससे पहले 18 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ईडी का आरोप- पसंदीदा फर्मों को दिलाए गए काम

ईडी के मुताबिक, डीएमएफ की राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जारी की जाती है। जांच में आरोप है कि सरकारी पद और अधिकारियों पर प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनिंदा फर्मों को काम दिलाए गए। इसके बदले 20 से 25 प्रतिशत तक कमीशन लिया गया।

47.17 करोड़ के भुगतान का भी जिक्र

ईडी ने कोर्ट को बताया कि डीएमएफ की बड़ी राशि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के जरिए खर्च की गई। एजेंसी का आरोप है कि टुटेजा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ललित भंसाली, यश नाहटा और सतपाल सिंह चाबड़ा से जुड़ी फर्मों को काम दिलाने में भूमिका निभाई। जांच में मां गंगा एंटरप्राइजेज और यश एंटरप्राइजेज को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच करीब 47.17 करोड़ रुपए के भुगतान का जिक्र किया गया है।



कोर्ट ने कहा...अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों,व्हाट्सऐप चैट और संबंधित लोगों के बयानों से प्रथम दृष्टया टुटेजा की भूमिका सामने आती है। मामले की गंभीरता और उनकी भूमिका को देखते हुए अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे आरोपियों को मिली नियमित जमानत का लाभ टुटेजा को नहीं दिया जा सकता। उन्हें लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर राहत मिली थी, जबकि टुटेजा ने गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत मांगी थी।

व्हाट्सऐप चैट और कारोबारियों के बयानों का हवाला

सुनवाई के दौरान ईडी ने टुटेजा के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में मिले व्हाट्सऐप चैट, कारोबारियों के बयान और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे। एजेंसी का दावा था कि इनसे काम दिलाने और कमीशन वसूली में टुटेजा की भूमिका सामने आती है। वहीं, टुटेजा की ओर से आरोपों को निराधार बताया गया। उनके वकीलों ने दलील दी कि वे डीएमएफ से जुड़े विभाग में पदस्थ नहीं थे और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष मनी ट्रेल भी नहीं है। उन्होंने दूसरे आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देकर राहत मांगी थी।

ट्रायल पर नहीं पड़ेगा आदेश का असर

एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए साफ किया कि जमानत याचिका पर की गई टिप्पणियों का मुख्य मुकदमे की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा।

महासमुंद में गर्म डस्ट गिरने से 5 मजदूर झुलसे

करणी स्टील-प्लांट में सफाई के दौरान हादसा,35 से 75% तक जले

महासमुंद,26 नवम्बर 2026। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र स्थित करणी कृपा पावर स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। 24 नवंबर की रात औद्योगिक भट्ठी की सफाई के दौरान गर्म डस्ट 5 मजदूरों पर गिर गया। हादसे में सभी मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए रायपुर के कालड़ा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। यहां बर्न यूनिट में उनका इलाज चल रहा है।



मिथिलेश्वर 75 प्रतिशत तक झुलसे : जानकारी के मुताबिक, हादसा ग्राम खैरझिटी-कौंवाझर के बीच स्थित प्लांट में हुआ। पांचों मजदूर भट्ठी की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान भट्ठी में जमा गर्म डस्ट अचानक उनके ऊपर गिर गया। डस्ट पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। इसकी चपेट में आने से सभी मजदूर झुलस गए। हादसे के बाद प्लांट प्रबंधन ने एंबुलेंस से घायलों को रायपुर भेजा। डॉक्टर सुनील कालड़ा के अनुसार, मिथिलेश्वर 75 प्रतिशत, लाल सिंह 45 प्रतिशत, राजकुमार 35 प्रतिशत, भागवत 55 प्रतिशत और हेमंत 60 प्रतिशत तक झुलसे हैं। सभी की हालत गंभीर बताई गई है।

पहले भी हो चुके हैं हादसे : प्लांट की औद्योगिक भट्ठी में गर्म डस्ट की चपेट में आने से पिछले तीन-चार साल में कई हादसे होने की जानकारी सामने आई है। जिसमें मजदूरों की मौत भी हो चुकी है।

सुरक्षा इंतजामों की जांच जरूरी : भट्ठी की सफाई जैसे जोखिम भरे काम में डस्ट का पूरी तरह ठंडा होना और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। यह जांच का विषय है कि हादसे के समय डस्ट का तापमान जांचा गया था या नहीं। मजदूरों को जरूरी सुरक्षा उपकरण दिए गए थे या नहीं और सफाई के दौरान तय सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं।

प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग : लगातार हादसों की जानकारी सामने आने के बाद प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग उठ रही है। प्रशासन और औद्योगिक सुरक्षा विभाग को घटना की जांच कर यह पता लगाना चाहिए कि हादसा किन कारणों से हुआ। जांच में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता लेखक कनक तिवारी का निधन

प्रोफेसर से पत्रकार और फिर बने वकील
संविधान-आदिवासी अधिकारों पर लिखी कई किताबें

रायपुर,26 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता, गांधीवादी चिंतक और लेखक कनक तिवारी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दुर्ग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कनक तिवारी का जन्म 26 जुलाई 1940 को हुआ था। वे गांधीवादी विचारधारा,भारतीय संविधान और सामाजिक विषयों पर अपनी समझ और लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लंबे समय तक लेखन के जरिए इन विषयों पर अपनी बात रखी। जानकारी के मुताबिक कनक तिवारी की बेटी फिलहाल सिंगापुर में रहती हैं। उनके सिंगापुर से दुर्ग पहुंचने के बाद शुक्रवार को पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

प्रोफेसर से पत्रकार और फिर बने वकील

कनक तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में की थी। करीब 8-9 साल तक उन्होंने कॉलेजों में पढ़ाया। इसके बाद पत्रकारिता में आए। वे पीटीआई,नवभारत टाइम्स,नवभारत और नागपुर टाइम्स जैसे संस्थानों से जुड़े रहे। उन्होंने 1971 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ पास की। इसके बाद वकालत शुरू की। कानून के साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी उनकी गहरी पकड़ थी।

शंकर गुहा नियोगी के कानूनी मामलों से भी जुड़े रहे...

छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन के चर्चित नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद उनके जमानत और कानूनी मामलों से जुड़े प्रसंगों में भी कनक तिवारी की भूमिका का उल्लेख मिलता है। वे अदालत में दलील रखने तक सीमित नहीं रहे।

पत्नी का गैर मर्द से संपर्क रखना मानसिक क्रूरता..

हाईकोर्ट बोला...शारीरिक संबंध का सबूत जरूरी नहीं

बातचीत करना,घर बुलाना भी आधार...तलाक मंजूर

बिलासपुर,26 नवम्बर 2026। पति की आपत्ति के बावजूद पत्नी का दूसरे पुरुष से लगातार संपर्क बनाए रखना। उससे मिलना वैवाहिक जीवन में मानसिक क्रूरता के समान है। इसके लिए हर मामले में शारीरिक संबंधों का प्रत्यक्ष प्रमाण होना जरूरी नहीं है। पत्नी के दूसरे पुरुष से लगातार फोन पर बातचीत करने,पति की गैरमौजूदगी में उसे घर बुलाने, उसके साथ बाहर जाने जैसी गतिविधियां भी अहम है। जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच तलाक के मामले में यह टिप्पणी की। दरअसल,शादी के 32 साल बाद पति ने पत्नी पर दूसरे पुरुष से संबंध होने का आरोप लगाते हुए तलाक मांगा था। फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए पति की तलाक की अपील मंजूर कर ली। दरअसल, मामला कोरिया जिले के बैकुंठपुर निवासी दंपती का है। दोनों की शादी साल 1994 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उनके एक बेटा और दो बेटियां हैं। पति का आरोप था कि पत्नी का दूसरे पुरुष से संबंध है। मना करने के बावजूद वह उससे बातचीत करती रही,जिससे उसकी मैरिड लाइफ प्रभावित हुई। इसी आधार पर पति ने तलाक की मांग की थी।

फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी खारिज की : पति ने मानसिक प्रताड़ना और दूसरे पुरुष से संबंध होने का आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी।



कोर्ट बोला- परिस्थितिजन्य सबूत भी अहम

हाईकोर्ट ने कहा कि,शादी के बाद संबंधों के मामलों में प्रत्यक्ष सबूत जुटाना हमेशा संभव नहीं होता। हर मामले में फोन रिकॉर्डिंग, वीडियो या दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में परिस्थितिजन्य सबूत और गवाहों के बयानों का एक साथ मूल्यांकन करना जरूरी है। कोर्ट के मुताबिक, शारीरिक संबंध साबित नहीं होने के बावजूद दूसरे पुरुष से लगातार बातचीत करना,पति की गैरमौजूदगी में उसे घर बुलाना और उसके साथ बाहर जाना जैसी गतिविधियां मानसिक क्रूरता के आकलन में अहम हो सकती हैं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अपील स्वीकार कर ली।

बेटी बोली- समझाने के बाद भी मां ने बातचीत नहीं रोकी...

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बेटी ने बताया कि,उसकी मां एक व्यक्ति से लगातार फोन पर बात करती थी। परिवार के लोगों ने उसे समझाया, लेकिन उसने बातचीत बंद नहीं की।

बेटा बोला- दूसरे व्यक्ति के साथ बाहर जाती थी मां

बेटे ने भी गवाही दी है कि पिता की गैरमौजूदगी में वह व्यक्ति घर आता था। बच्चों के पिता को इसकी जानकारी देने पर मां उन्हें डांटती थी। बेटे के मुताबिक,एक बार मां घर छोड़कर उस व्यक्ति के घर भी चली गई थी।

जनदर्शन में जरूरतमंदों को मिला मुख्यमंत्री का संबल,उपचार के लिए तत्काल प्रदान की आर्थिक सहायता

सात वर्षीय आवान की थेरेपी के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदान किया 40 हजार रुपए का चेक,तीन जरूरतमंदों को उपचार के लिए मिली 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता

रायपुर,26 नवम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में उपचार के लिए आर्थिक सहायता की उम्मीद लेकर पहुंचे जरूरतमंदों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और तत्काल मदद उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपचार कराने में असमर्थ तीन जरूरतमंदों को कुल 55 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री की इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को उपचार कराने में राहत मिली है। जनदर्शन में रायपुर से अपने सात वर्षीय सुपुत्र मोहम्मद आवान के उपचार के लिए सहायता मांगने पहुंचे मोहम्मद आरिफ ने मुख्यमंत्री साय को अपनी आर्थिक परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित है और उसकी नियमित थेरेपी में प्रतिमाह लगभग 40 हजार रुपए का खर्च आता है। दुर्घटना में चोटिल होने के बाद उनके पास वर्तमान में रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसे में परिवार की आजीविका चलाने के साथ ही बच्चे की नियमित थेरेपी का खर्च वहन करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। मुख्यमंत्री साय ने पिता की व्यथा को संवेदनशीलता के साथ सुना और बच्चे की थेरेपी के लिए तत्काल 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने आवान के बेहतर स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस सहायता से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवार को बच्चे की थेरेपी जारी रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार पाटन से जनदर्शन में पहुंचे ज्ञानेश कुमार साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे पेट संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपचार कराने में असमर्थ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री साय ने उनकी समस्या को सुनकर उपचार के लिए तत्काल 10 हजार रुपए का चेक प्रदान किया।



प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)